₹ 10

www.kewalsachtimes.com

मार्च 2024

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

RNI NO.-BIHBIL/2011/49252, DAVP NO.-131729, POSTAL REG. NO.:-PS.-78

केन्द्रीय कारागार तिहाड़ (दिल्ली सरकार)
संख्या - 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9

अरविंद केजरीवाल

आबकारी घोटाले का सरगना एवं षड्यंत्रकारी!

जन-जन की आवाज है केवल सच

आत्म-निर्भर बनने वाले युवाओं को सपोर्ट करें

आपका छोटा सहयोग, हमें मजबूती प्रदान करेगा

www.kewalsach.com

www.kewalsachlive.in

-: सम्पर्क करें :-

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14, मकान संख्या-28/14,

कंकड़बाग, पटना (बिहार)-800020, मो०:-9431073769, 9308815605

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ

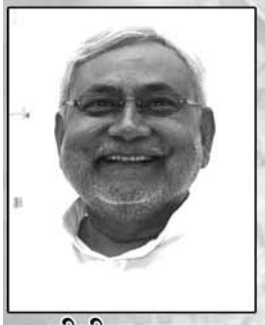

नीतीश कुमार
01 मार्च 1951

मेरी कॉम
01 मार्च 1983

शंकर महादेवन
03 मार्च 1967

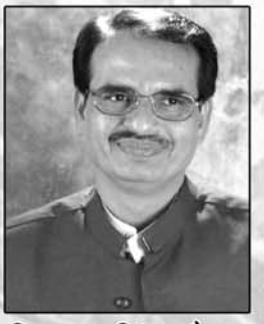

शिवराज सिंह चौहान
05 मार्च 1959

अनुपम खेर
07 मार्च 1955

नवीन जिंदल
09 मार्च 1970

उमर अब्दुल्लाह
10 मार्च 1970

श्रेया घोषाल
12 मार्च 1984

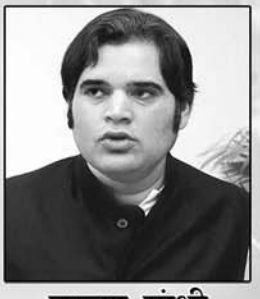

वरूण गांधी
13 मार्च 1980

अमीर खान
14 मार्च 1965

हनी सिंह
15 मार्च 1984

राजपाल यादव
16 मार्च 1971

सानिया नेहवाल
17 मार्च 1990

रानी मुखर्जी
21 मार्च 1978

स्मृति जुबैद ईरानी
23 मार्च 1976

इमरान हाशमी
24 मार्च 1979

मधु
26 मार्च 1972

प्रकाश राज
26 मार्च 1965

शीला दीक्षित
31 मार्च 1938

मीरा कुमार
31 मार्च 1945

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House No.-28/14, Road No.-14, kankarbagh, Patna- 8000 20 (Bihar) Mob.-09431073769,
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Vaishnavi Enclave, Second Floor, Flat No. 2B, Near-firing range, Bariatu Road, Ranchi- 834001
E-mail :- editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha
A-68, 1st Floor, Nageshwar talla, Shastri Nagar, New Delhi-110052
Mob.- 09868700991, 09955077308
kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube, 131 Chitranjan Avenue, Near- md. Ali Park, Kolkata- 700073 (West Bengal)
Mob.- 09433567880, 09339740757

ADVERTISEMENT RATES PER ISSUE

	AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
COLOUR	Cover Page	3,00,000/-	N/A
	Back Page	1,00,000/-	65,000/-
	Back Inside	90,000/-	50,000/-
	Back Inner	80,000/-	50,000/-
	Middle	1,40,000/-	N/A
	Front Inside	90,000/-	50,000/-
	Front Inner	80,000/-	50,000/-

	AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
B & W	Inner Page	60,000/-	40,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट **www.kewalsachtimes.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

व्यापार बन गया चिकित्सा सेवा

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com

पृथ्वी पर भगवान की उपाधि से नवाजे जाने वाले Doctor अब मरीजों की सेवा नहीं बल्कि मरीजों का व्यापार करते हैं। धड़ल्ले से देश के विभिन्न राज्यों के शहरो में प्राईवेट Hospital खुल रहे हैं। जिस प्रकार Hotel में Menu के अनुसार किसी भी Program का पैकेज बनता है उसी प्रकार Hospital भी Hotel का रूप लेकर मरीजों एवं उनके परिजनों का सुविधा के नाम पर जमकर उगाही कर रहा है। जहां पहले Doctor नब्ज देखकर मरीज का स्थिति का मुआयना करते थे लेकिन आज वर्त्तमान समय में अंधाधुंध (कमीशन) कमाई के चक्कर में मरीज का इतना जाँच कराते हैं कि मरीज एक बीमारी से निजात पाते - पाते अन्य कई बीमारी के विषय में जानकर मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। अगर सबकुछ जांच के उपर ही आधारित हो गया तो फिर Doctor का क्या काम? सेवा भाव का महत्व अर्थयुग में समाप्त होता जा रहा है और Doctor में यह भाव भी विलुप्त होता जा रहा है क्योंकि जिस प्रकार का कमीशन Medicine और Pathology के क्षेत्र में है की दूसरा वस्तु का व्यापार करने वाले भी भौच्चक रह जायें। लाभ के लिए किस हद तक व्यापारी गिर सकता है यह देखना है तो चिकित्सा सेवा को नजदीक से समझना होगा और प्रत्यक्ष रूप से Govrnent की भूमिका भी शामिल है। इंश्योरेंस कंपनी के बढ़ते वर्चस्व की वजह से Public भी मूडिकल बीमा कराकर अपना बचत तो करती है लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलीभगत करके Doctor और Hospital इस सेवा के क्षेत्र को लाभ के लिए मरीज के जान से खेलने लगे हैं। मरीज को स्वस्थ्य करने के बजाय कैसे मरीज से ज्यादा से ज्यादा धन उगाही करें उसमें मशगूल हैं।

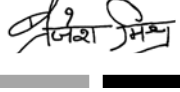

India जैसे देश में जहां धर्म और मानवता को प्राथमिकता दिया जाता है और सेवा भाव को काफी प्रभावकारी माना जाता रहा है लेकिन 21वीं सदी के दौर में Health Service पूर्णरूपेण व्यापार में तब्दील हो चुकी है। सरकार केन्द्र की हो या राज्य की अपनी Public के लिए अरबों रूपये स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में खर्च कर रही है ताकि आवाम को गंभीर से गंभीर बीमारी से भी बचाया जा सके। एक कालखंड में Doctor का मतलब God होता था लेकिन आज भगवान BusinessMan बन चुका है और उसको मरीज के जीवनदान से ज्यादा उसको सर्वाधिक Profit कैसे होगा उसी के जुगाड़ में लगा हुआ है भले ही मरीज का Death क्यों न हो जाये। इस व्यापार में स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि कई दिन पूर्व मरे हुए मरीजों से भी धन उगाही करके उनके परिजन के भावनाओं का भी कत्ल कर रहे हैं। Doctor पर से आमलोगों का विश्वास भी उठता जा रहा है क्योंकि पहले चिकित्सा क्षेत्र को सेवा के रूप में ख्याति थी लेकिन आज यह क्षेत्र राजनीति की तरह बदनाम हो चुकी है और खुद इससे जुड़े लोगों को भी अपने बिरादरी पर भरोसा नहीं रहा है। प्रतियोगी दौर में जहां Doctor बनने के लिए ही करोड़ों रूपये कर्ज लेकर खर्च करना पड़ता है और अगर अपना क्लिनिक या Hospiatl खोलना हो तो सबकुछ दाव पर लग जाता है जिसकी वजह से भी Health Service सेवा के बजाय Business बनकर रह गया है। सभी Doctor अपना नीजी Hospital नहीं खोल सकते और न ही सबको सरकारी सेवा में स्थान मिल जाये ऐसे में ON Call किसी न किसी Hospital के यहां आपको सेवा देनी पड़ती है और आप जितनी कमाई करके उस Hospital प्रबंधन को देंगे उसका कुछ प्रतिशत और सैलरी पैकेज के रूप में मिलेगा। किसी मरीज को जीवन दान देने और स्वस्थ करने से ज्यादा चिंता इस बात का भी है कि हम अपने पैकेज के अनुसार उस Hospital में सेवा दे रहे हैं या नहीं। वर्तमान समय में किसी भी बीमारी के अच्छे विशेषज्ञ की संख्या न के बराबर हैं और जो बचे हैं जिनका पहचान है वह अर्थयुग में पैकेज के प्रभाव में आकर अपनी चिकित्सीय सेवा को व्यावसाय के रूप में देख रहे हैं। आमजनता भी Health इंश्योरेस कार्ड लेकर अपनी सेविंग को बीमारी में जहां बचाने की कोशिश कर रही है वहीं कई कंपनियां बीमा भी बीमारी देखकर करती है और जो सारी बीमारी में कवरेज देती है उसका प्रिमियम ज्यादा होता है। सरकार भी स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में बड़े स्तर पर काम कर रही है लेकिन इससे आमजन को जितना राहत मिलता है उससे कहीं ज्यादा प्राईवेट Hospital प्रबंधन को मिलता है और देश के भीतर ईमानदारी से अगर जांच हो तो सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। सरकार बीमा देकर जहां जनता के बीच भगवान बनने की कोशिश कर रही है वहीं Health Department और Hospital प्रबंधन की सांठ-गांठ ने सरकारी खजाने का जमकर दोहन किया है। वैसे में आजकल के Doctor किस प्रकार की शिक्षा ले रहे हैं और उनका अनुभव कैसा है यह इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि वह मरीज के बीमारी के विषय में बगैर Pathology जांच के कोई दवा तक नहीं लिखते वहीं सरकारी का एम्स हो सफदरजंग, देश के किसी भी राज्य में सरकारी अस्पताल की हालत क्या है यह सरकार को भी पता है और सुप्रीम कोर्ट को भी लेकिन इसपर कोई ठोस कानून नहीं रहने की वजह से स्वास्थ्य सेवा में बड़े स्तर पर गोरखधंधा है। सरकारी अस्पताल में विशेष जल्दी देखते ही नहीं बल्कि चिकित्सा की शिक्षा ले रहे छात्रों के भरोसे सरकार अस्पताल मरीजों के जान के साथ खेल रहे हैं। आज Doctor किसी भी कंपनी का दवा लिखने के लिए क्या -क्या नहीं लेते। गाड़ी, बंगला, विदेश का टूर पैकेज तथा घर की जरूरत के सभी सामान की पूर्ति दवा कंपनी और पैथेलॉजी केन्द्र से पूरी की जाती है। ऐसे में 95 फिसदी Doctor बिना वजह का भी जांच कराते हैं और एक -दो दवा आवश्यकता नहीं रहते पर भी अपने पूर्जे में लिखते हैं क्योंकि उनका खर्च उठाने वाले समय पर सेवा देते रहें, भले हीं मरीज को बीमारी से निजात मिले या नहीं। अब तो स्थिति भयावह होती जा रही है कि 15 दिन पर ही Doctor फीस लेने लगे हैं। जिस Doctor की जितनी ज्यादा फीस वह उतना ही काबिल समझा जाता है। Advertisement के दौर में आवाम ठगी का शिकार हो रही है क्योंकि सरकार से वेतन उठाने वाले Docotor भी कमीशन के चक्कर में प्राईवेट Hospital में रेफर कर देते हैं। Hospital प्रबंधन मरीज के परिजन का मनोभाव को समझ लेते हैं कि मरीज और परिजन के बीच किस प्रकार की भावना है और उसके बाद चिकित्सा के नाम पर शुरू हो जाता है दोहन। मरीज को इतनी दवा दे दी जाती है जिसकी वजह से भी मरीज की हालत खराब हो जाती है लेकिन जितनी ज्यादा दवा और जांच होगा उतना ही बिल होगा। मरीज की जान बचेगी उसकी कोई गारंटी नहीं लेकिन बिल भुगतान के बगैर लाश भी नहीं मिल पायेगा, क्योंकि Hopsital में इतने गनर और बाउंसर हैं की उनका मुकाबला असंभव हो जाता है। चिकित्सा सेवा नहीं बल्कि बिना नुकसान के 100 प्रतिशत मुनाफा के व्यापार है इसलिए पूंजीपति इस क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं। मरे हुए का ईलाज करने वाला Doctor को भगवान का दर्जा देना उचित नहीं है। यही वजह है कि किसी भी शहर में एक दो Doctor का नाम होता है जबकि वहां हजारों की संख्या में Doctor हैं। सरकार अगर इस मामले को लेकर गंभीर नहीं हुई तो सरकारी खजाना भी लूटता रहेगा और आवाम की जान भी जानवरों की तरह कसाई की तरह काटे जाते रहेंगे।

KEWAL SACH TIMES

A National Magazine

वर्षः- 13, अंकः- 153 माहः- मार्च 2024 रू. 10/-

Editor

Brajesh Mishra 9431073769
6206889040
8340360961

editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach@gmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

Principal Editor

Arun Kumar Banka 7782053204
Surjit Tiwary 9431222619
Nilendu Kumar Jha 9431810505

General Manager (H.R)

Triloki Nath Prasad 9308815605

General Manager (Advertisement)

Manish Kamaliya 6202340243
Poonam Jaiswal 9430000482

Joint Editor/Lay-out Editor

Amit Kumar 9905244479
amit.kewalsach@gmail.com

Legal Editor

Amitabh Ranjan Mishra 8873004350
S. N. Giri 9308454485

Asst. Editor

Mithilesh Kumar 9934021022
Sashi Ranjan Singh 9431253179
Rajeev Kumar Shukla 7488290565
Kamod Kumar Kanchan 8971844318

Sub. Editor

Arbind Mishra 6204617413
Prasun Pusakar 9430826922
Brajesh Sahay 7488696914

Bureau Chief

Sanket kumar Jha 7762089203
Sagar Kumar 9155378519

Bureau

Sridhar Pandey 9852168763
Sonu Kumar 8002647553

Photographer

Mukesh Kumar 9304377779

प्रदेश प्रभारी

दिल्ली हेड

संजय कुमार सिन्हा 9868700991

झारखण्ड हेड

ब्रजेश मिश्र (2) 7979769647
7654122344

पश्चिम बंगाल हेड

अजीत दुबे 9433567880
9339740757

मध्यप्रदेश हेड

अभिषेक पाठक 8109932505
8269322711

छत्तीसगढ़ हेड

आवश्यकता है

उत्तर प्रदेश हेड

निर्भय कुमार मिश्रा 9452127278

उत्तराखण्ड हेड

आवश्यकता है

महाराष्ट्र हेड

आवश्यकता है

गुजरात हेड

आवश्यकता है

आंध्र प्रदेश हेड

आवश्यकता है

राजस्थान हेड

आवश्यकता है

पंजाब हेड

आवश्यकता है

हरियाणा हेड

आवश्यकता है

राजस्थान हेड

आवश्यकता है

उड़ीसा हेड

आवश्यकता है

आसाम हेड

आवश्यकता है

हिमाचल हेड

आवश्यकता है

दिल्ली कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
A-68, 1st Floor,
नागेश्वर तल्ला, शास्त्रीनगर, न्यू
दिल्ली-110052
मो०- 9868700991, 9431073769

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल- 700073
मो०- 9433567880, 9339740757

झारखण्ड कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
वैष्णवी इंक्लेव, द्वितीय तल,
फ्लैट नं- 2बी
नियर- फायरिंग रेंज
बरियातु रोड, राँची- 834001
मो०- 9308815605

मध्यप्रदेश कार्यालय

केवल सच टाइम्स,
द्विभाषीय मासिक पत्रिका,
द्वारा- अभिषेक कुमार पाठक
हाउस नं.-28, हरसिद्धि कैम्पस
खुशीपुर, चांबड़
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462010
मो०- 8109932505,

विशेष प्रतिनिधी

भारती मिश्र 8521308428
बेंकटेश कुमार 8210023343

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

प्रकाशित आलेख पर आप अपना सुझाव एवं प्रतिक्रिया अवश्य दें।

केवल सच टाइम्स

द्विभाषीय मासिक पत्रिका

हमारा पता है

पूर्वी अशोक नगर, रोड नं.-14,
मकान संख्या:- 14/28, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)

सम्पर्क करें:- 9431073769, 8340360961

हमारा ई-मेल

editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

फरवरी 2024

एक नए युग का

मिश्रा जी,

दिल को सुकून और गर्व महसूस करने वाली खबर ''**एक नए युग का ऐतिहासिक शुभारंभ**'' को अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख राष्ट्रीय स्वय सेवक संघ के रामलाल ने श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर लिखी। 2024 का प्रारंभ भगवान श्रीराम मंदिर में प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा से शुरू हुआ और 500 वर्षों का इतिहास को जिवंत कर दिया है। मोदी की सरकार ने भारतीय संस्कृति को वह धार दिया है जिसकी चर्चा कई युगों युगों तक होगी। विभिन्न धर्मो, पंथों और विभिन्न देशों के लोग इस शुभ घड़ी के साक्षी बने। वैसे तो इस अंक की सभी खबरें अच्छी है लेकिन दिल को सुकून इसी खबर से मिली।

● **मोहन सिंह, अम्बिकापुर, छ०ग०**

गारंटी

संपादक महोदय,

आपकी पत्रिका केवल सच टाइम्स का संपादकीय बेजोड़ एवं समसामयिक विषयों पर आधारित होता है। फरवरी 2024 अंक में प्रकाशित संपादकीय ''**वारंटी के दौर में गारंटी**'' में आपने वर्त्तमान समय की उन तमाम घटनाओं एवं राजनीति की ओच्छी हरकतों के साथ-साथ राजनीति में विश्वास पर सटीक विश्लेषण करते हुए खबर को लिखा है। सच्चाई यही है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति के गिरते स्तर एवं जनता का उठता विश्वास को फिर से जागृत किया इस वजह से वारंटी के दौर में गारंटी को कायम किया और 2014 एवं 2019 के बाद 2024 में भी विश्वास कर रहे हैं।

● **विजय मिश्र, रेलवे कॉलोनी, मुगलसराय, यूपी**

पलटू चाचा पलटे

संपादक महोदय,

बेबाक एवं बिना लाग-लपेट की खबरों की वजह से आपकी चर्चा सभी राजनीतिक गलियारे में होती है। फरवरी 2024 अंक में पत्रकार संतोष पाठक की खबर ''**पलटू चाचा फिर पलटे**'' में चाचा की पलटीमार राजनीति की सही व्याख्या की है और फिर से पलटने की वजह को भी लिखने का साहस किया है। आज कलम किसी न किसी पार्टी की रखैल बनती जा रही हैं वहीं पलटू चाचा एवं भतीजे के द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर भी है। आनन-फानन में हुई बहाली का ढ़िंढोरा भतीजा पीट रहा है। यह खबर सही मायने में सरकार के द्वारा बहाली प्रक्रिया में हुई भूल को आईना दिखा रहा है। संतोष पाठक की खबर काफी प्रशंसनीय है।

● **प्रवीण ठाकुर, एस के पुरी पार्क, पटना**

हैवान शाहजहाँ

संपादक महोदय,

मैं केवल सच टाइम्स, पत्रिका का नियमित पाठक हूं और सभी खबरों को पढ़ता हूं। फरवरी 2024 अंक में पत्रकार अमित कुमार की धारदार खबर पश्चिम बंगाल के शेख की हैवानियत पर लिखा है। ''संदेशखाली का हैवान शाहजहाँ शेख'' की हरकतों के साथ बंगाल में चल रही दोगली राजनीति पर बहुत लंबा लेकिन सटीक एवं पूर्ण विश्लेषण के साथ खबर को पाठकों के समक्ष अमित जी ने रखा है वह काबिले तारिफ है। हत्या, बलात्कार, लूट, जमीन हड़पना और न जाने किस किस अपराध में संल्पित होने के बावजूद पुलिस के द्वारा शेख की गिरफ्तारी नहीं होती है। राजनीति का गिरता स्तर एवं बंगाल की खूनी राजनीति पर धुआंधार खबर को लिखने के लिए साधुवाद।

● **दीनकर सहाय, बाबू बाजार, कोलकाता**

दावेदारी

मिश्रा जी,

केवल सच टाइम्स पत्रिका की फरवरी अंक में प्रकाशित खबर ''कल्पना बनाम सीता की दावेदारी के बीच विजयी हुए चंपई'' में झारखंड के मुख्यमंत्री की राजनीति पर सही विषय को पाठकों के बीच रखा गया है। ईडी के द्वारा गिरफ्तार किये गये देश के पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद प्रदेश का अगला मुख्यि कौन रहेगा की राजनीति पर काफी कूटनीति हुई लेकिन किस्मत चंपई सोरेन की हांथ लगी। लोग बात यही करते हैं कि लालू यादव की तरह हेमंत सोरेन भी अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री का ताज सौपेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसकी वजह को पड़ताल करती खबर काफी विचारणीय है। राजनीति की खबर काफी सटीक एवं बेवाक होती है।

● **मनोज उरांव, करमटोली चौक, राँची**

सत्याग्रह का सत्यानाश

ब्रजेश जी,

फरवरी 2024 अंक में अमित कुमार की दूसरी खबर ''**सत्याग्रह का सत्यानाश किसान आन्दोलन**'' में केवल सच टाइम्स पत्रिका ने सकरात्मक पत्रकारिता का परिचय दिया है। जिस प्रकार किसान आन्दोन MSP को लेकर आन्दोलन कर रही है और आन्दोलन के आड़ में गंदी राजनीति की जा रही है, उससे अन्य राज्यों के किसान भी अब शर्मीदा होने लगे हैं। MSP की मांग की आंड में PM मोदी को हटाने की कूटनीति का राजनीतिक खेल पर काफी जानकारीप्रद एवं सत्याग्रह जैसे आन्दोलन को सत्ता की प्राप्ति के लिए सत्यानाश का खेल को उजागर करने का काम आपके पत्रकार ने बखूबी किया है जो बधाई के पात्र हैं।

● **जसप्रीत कौर, मयूर बिहार, नई दिल्ली**

अन्दर के पन्नों में

18

27

ISRO successfully lands 30

40

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक
'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**
राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)
पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
09431016951, 09334110654

डॉ. सुनील कुमार

शिशु रोग विशेषज्ञ सह मुख्य संरक्षक
'केवल सच' पत्रिका
एवं 'केवल सच टाइम्स'
एन.सी.- 115, एसबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी,
लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना- 800020
फोन- 0612/3504251

श्री सज्जन कुमार सुरेका

मुख्य संरक्षक
'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**
डी- 402 राजेन्द्र विहार, फॉरेस्ट पार्क
भुवनेश्वर- 751009 मो-09437029875

सुधीर कुमार

मुख्य संरक्षक सह निदेशक **''मगध इंटरनेशनल स्कूल''** टेकारी
'' केवल सच '' पत्रिका **एवं '' केवल सच टाइम्स ''**
9060148110
sudhir4s14@gmail.com

श्री आर के झा

मुख्य संरक्षक
'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**
EX. CGM, (Engg.) N.B.C.C
08877663300

एक नजर

संपादकीय व प्रधान कार्यालय:-

- पूर्वी अशोक नगर, रोड नं:-14, मकान संख्या:- 28/14, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
  e-mail:- kewalsach@gmail.com,
  editor.kstimes@rediffmail.com
  kewalsach_times@rediffmail.com
- स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा जय हिन्द प्रेस कंकड़बाग पटना-800020 से मुद्रित एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। **RNI NO.- BIHBIL/2011/49252**
- पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।
- सभी प्रकार के वाद - विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।
- आलेख पर किसी को कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।
- किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- सभी पद अवैतनिक हैं।
- विज्ञापन की सत्यता की जाँच आप अपने स्तर पर कर लें।
- फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)
- कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।
- **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**
- भुगतान BRAJESH MISHRA को ही करें। किसी प्रतिनिधि को नगद न दें।

A/C No.	:-	20001817444
BANK	:-	State Bank Of India
IFSC Code	:-	SBIN0003564
PAN No.	:-	AKKPM4905A

Contributions/Donations are Invited for the Welfare of Elders/Sr. Citizens for the establishment of "APNA GHAR" A home for Sr. Citizens of Bihar & Jharkhand Proposed to be Constructed Under the ageas of " KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN".

KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN

Registered Under the Indian Society Act 21, 1880

East Ashok Nagar, Road No.-14,
Kankarbagh, Patna - 800020

Contact No. :- 09431073769, 9955077308, 9308727077

E-mail :- kewalsachsamajiksansthan33@gmail.com

Reg. No. : 1141 (2009-10), Income Tax No. :12AA/2505-8 | 80 जी (5)/तक०/2013-14/1060-63

APNA GHAR

Now in the State of Bihar & Jharkhand

Help the helpless Elders/Sr. Citizen. For which your Contribution and Donation are essential.
Your Coopertation in this direction can make a diffrence in the lives of many Sr. Citizens.

KEWAL SACH SAMAJIK SANSTHAN

A/C No.	-	**0600010202404**
Bank Name	-	**United Bank of India**
IFSC Code	-	**UTBIOKKB463**
Pan No.	-	**AAAAK9339D**

अरविंद केजरीवाल आबकारी घोटाले का सरगना एवं षड्यंत्रकारी!

● अमित कुमार

ईडी की टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर जब पहुंची तभी ये कयास लगाए जाने लगे थे कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। रात करीब 9 बजे आप नेता अतिशी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की पुष्टि की और कहा कि पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने सर्वोच्च अदालत से इस मामले में तत्काल सुनवाई की अपील की है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि रात में ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास की पूरी तलाशी ली गई। सिर्फ 70,000 रुपये नकद में मिले, जिसे ईडी वापस कर गई। मुख्यमंत्री जी का मोबाइल ले लिया गया और उन्हें गिरफ्तार करके ले गए हैं। पूरे छापे में कोई गैरकानूनी पैसा, कागज या सबूत नहीं मिला। इस बीच मुख्यमंत्री आवास से बाहर भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा होकर नारेबाजी करने लगे। सीएम आवास के बाहर दिल्ली पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी थी। दिल्ली पुलिस ने आप के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इस हंगामे के बीच ईडी केजरीवाल को ईडी हेडक्वार्टर ले गई। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने इसे 'लोकतंत्र की हत्या' बताया तो पार्टी के राज्य सभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि 'भारत में अघोषित इमरजेंसी है।' इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अरविंद केजरीवाल को आठ बार समन जारी किए थे। पिछले साल नवंबर और दिसंबर में दो, इस साल जनवरी में दो, फरवरी में तीन और मार्च में एक समन। इन सभी समन में केजरीवाल एक बार भी पूछताछ के लिए नहीं गए। अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी से अंतरिम राहत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था,

जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। बीजेपी सांसद रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि यह कानूनी प्रक्रिया है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उचित कार्रवाई के दृष्टिकोण से हो रही है, जिसमें उन्हें न्यायालय से भी कोई राहत नहीं मिली। कानून को अपना काम करने दिया जाए। उधर, विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि उन्हें लगता है कि इससे इंडिया गठबंधन हिल जाएगा या डिरेल हो जाएगा, वे गलत सोच रहे हैं। इन कदमों से स्पष्ट हो जाता है कि बीजेपी को अपनी हार दिख रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजद नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, सपा नेता अखिलेश यादव, एनसीपी (एससीपी) नेता शरद पवार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, टीएमसी नेता कुणाल घोष समेत कई नेताओं ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की निंदा की है।

बताते चले कि प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 'आबकारी घोटाले' के 'सरगना' एवं 'षड्यंत्रकारी' हैं और इसके पास उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह मानने के कारण हैं कि वे मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के दोषी हैं। 'घोटाले' से जुड़े धनशोधन मामले में एजेंसी द्वारा आम आदमी पार्टी नेता की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका का विरोध करते हुए, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि राजनीतिक दल, जो अपराध की आय का 'प्रमुख लाभार्थी' था, ने केजरीवाल के माध्यम से अपराध किया है। ईडी ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य व्यक्तियों की मिलीभगत से दिल्ली आबकारी घोटाले के सरगना और मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर आबकारी नीति 2021-22 बनाने में शामिल थे। एजेंसी ने कहा कि इस नीति का मसौदा 'साउथ ग्रुप' को दिए जाने वाले लाभों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था और इसे विजय नायर, मनीष सिसोदिया और 'साउथ ग्रुप' के प्रतिनिधि सदस्यों की मिलीभगत से बनाया गया था। ईडी ने कहा कि आप ने केजरीवाल के माध्यम से धनशोधन का अपराध किया है और इस तरह यह अपराध पीएमएलए, 2002 की धारा 70 के दायरे में आता है। इसने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली आबकारी घोटाले में अर्जित अपराध की आय की प्रमुख लाभार्थी है। अरविंद केजरीवाल आप की प्रमुख गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। जैसा कि गवाहों के बयान से स्पष्ट होता है कि वह पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और नीति बनाने के निर्णयों में भी शामिल थे।

गौरतलब है कि भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी और आईआईटी के छात्र रहे केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक जमीन 2011 के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में तैयार की थी। साल 2002 के शुरुआती महीनों में केजरीवाल भारतीय राजस्व सेवा से छुट्टी लेकर दिल्ली के सुंदरनगरी इलाके में एक्टिविज्म करने लगे। यहीं केजरीवाल ने एक गैर-सरकारी संगठन स्थापित किया जिसे 'परिवर्तन' नाम दिया गया। उन्हें पहली बड़ी पहचान साल 2006 में मिली जब 'उभरते नेतृत्व' के लिए उन्हें रेमन मैग्सेसे अवॉर्ड दिया गया। साल 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन में हुए कथित घोटाले की खबरें मीडिया में आने के बाद लोगों में भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा था। सोशल मीडिया पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन मुहिम शुरू हुई और केजरीवाल इसका चेहरा बन गए। केजरीवाल ने अपना पहला बड़ा धरना जुलाई 2012 में 'अन्ना हजारे के मार्गदर्शन में' जंतर-मंतर पर शुरू किया। 26 नवंबर 2012 को केजरीवाल ने अपनी पार्टी का विधिवत गठन की घोषणा की। केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी में कोई हाई कमान नहीं होगा और

राघव चड्ढ़ा

गोपाल राय

पवन खेरा

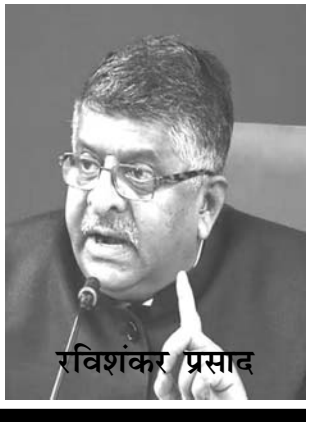
रविशंकर प्रसाद

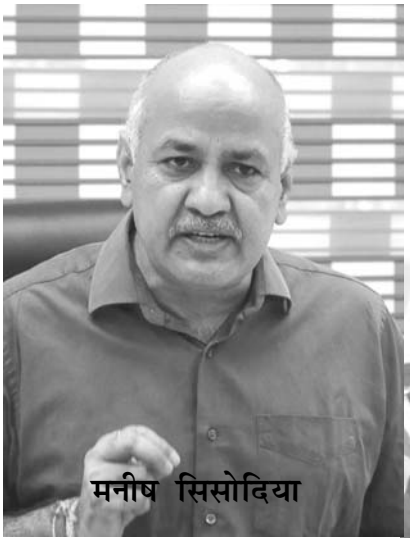
मनीष सिसोदिया

विजय नायर

अरविंद केजरीवाल

वो जनता के मुद्दों पर जनता के पैसों से चुनाव लड़ेंगे। केजरीवाल ने राजनीति का रास्ता चुना तो उनके गुरू अन्ना हजारे ने भी कह दिया कि वो सत्ता के रास्ते पर चल पड़े हैं। शुरुआती दिनों में अरविंद को जो मिल रहा था उसे वो पार्टी से जोड़ रहे थे। उनकी ये संगठनात्मक क्षमता ही आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। केजरीवाल ने ऐसे स्वयंसेवक जोड़े, जो भूखे रहकर भी उनके लिए काम करने के लिए तैयार थे। लाठी-डंडे खाने के लिए तैयार थे। इन्हीं स्वयंसेवकों के दम पर केजरीवाल ने 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा। राजनीति में पदार्पण करने वाली उनकी पार्टी ने 28 सीटें जीतीं। स्वयं केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से तत्कालीन सीएम शीला दीक्षित को पच्चीस हजार से अधिक वोटों से हराया। लेकिन उन्हें सरकार इन्हीं शीला दीक्षित की कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर बनानी पड़ी। केजरीवाल जल्द से जल्द जनलोकपाल बिल पारित कराना चाहते थे। लेकिन गठबंधन सरकार में साझीदार कांग्रेस तैयार नहीं थी। अंततः 14 फरवरी 2014 को केजरीवाल ने दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और फिर सड़क पर आ गए। कुछ महीने बाद ही लोकसभा चुनाव होने थे। केजरीवाल बनारस पहुँच गए लेकिन बनारस में केजरीवाल तीन लाख सत्तर हजार से अधिक मतों से हार गए। लेकिन इसके अगले साल ही दिल्ली के लिए हुए विधानसभा चुनावों में 70 में से 67 जीत कर केजरीवाल ने इतिहास बनाया और 14 फरवरी 2015 को फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री की शपथ ली। इस बीच राष्ट्रीय राजनीति में आम आदमी पार्टी का कद और बढ़ा है और उसके साथ ही केजरीवाल का भी। पंजाब में आप की सरकार है। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में पार्टी को बहुमत मिला तो यूपी के नगर निकाय चुनावों में पार्टी के करीब 100 उम्मीदवार जीते। पिछले गुजरात विधानसभा चुनावों में भी उसे आधा दर्जन से अधिक सीटों पर सफलता मिली और कई जगहों पर उसके उम्मीदवारों को अच्छा समर्थन मिला। पिछले साल ही चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया। इंडिया गठबंधन में शामिल होकर आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय मंच पर अपना कद बढ़ाने की कोशिश में है।

अन्ना हजारे के साथ आन्दोलन में केजरीवाल

बहरहाल, ईमानदारी का चोला पहनकर भ्रष्टाचार की गंगोत्री में चतुराई के साथ डुबकी लगाने वाले केजरीवाल अपने विभागीय मंत्रियों के साथ आबकारी घोटाले को अंजाम दिया और फिर मनीष सियोदिया और संजय सिंह की जेल यात्रा के बाद केजरीवाल को जेल भेजा जा चुका है। बता दें कि पिछले साल फरवरी में दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही दिल्ली की एक अदालत से कहा कि उन्हें और जेल में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। दिल्ली

के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल को बताया कि कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के धन शोधन मामले में उनके खिलाफ जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और उनके द्वारा जांच में बाधा डालने या सबूत नष्ट करने की कोई आशंका नहीं है। उन्होंने न्यायाधीश से यह भी कहा कि अगर अदालत उन्हें जमानत देने का फैसला करती है, तो वह अदालत द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त का पालन करने के लिए तैयार हैं। सिसोदिया फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। इससे पहले, ईडी ने कहा था कि मामला महत्वपूर्ण चरण में है और अगर रिहा किया गया, तो आरोपी जांच में बाधा डाल सकता है, जिसके बाद अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। ईडी का मामला आबकारी नीति के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। सीबीआई ने यह आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया था कि दिल्ली आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और एल-1 लाइसेंस को सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना बढ़ाया गया। सीबीआई के अनुसार, लाभार्थियों ने आरोपियों को "अवैध" लाभ पहुंचाया और जांच से बचने के लिए उनके बहीखातों में गलत प्रविष्टियां कीं। सीबीआई ने सिसोदिया को फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया और बाद में उन्हें तिहाड़ जेल से ईडी ने हिरासत में ले लिया। सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद सिसोदिया ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अब केजरीवाल स्वयं जेल के अंदर है और तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 2 में 14X8 की सेल में पहली रात अकेले गुजारी। उन पर सीसीटीवी कैमरे से लगातार नजर रखी जा रही है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही उन्हें सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कोर्ट से जेल में रहने के दौरान कुछ किताबें और अन्य सामान की मांग की है, जिसे जेल प्रशासन की ओर से मुहैया करवाया जाएगा। वे घर का बना खाना और दवाएं भी ले सकेंगे। शुगर लेवल अचानक गिरने की स्थिति में दिल्ली सीएम को ग्लूकोज, टॉफी, केला और ईसबगोल भी उपलब्ध कराया जाएगा। केजरीवाल को दैनिक इस्तेमाल के लिए सामान की एक किट दी गई है। इसमें बाल्टी, मग, तौलिया, नहाने और कपड़ा धोने का साबुन तथा ब्रश भी दिया गया है। उन्हें जेल की ओर से एक सेवादार भी मिलेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जेल प्रशासन को 6 लोगों की लिस्ट दी है। वे इन लोगों से मुलाकात कर सकेंगे। उसी नंबर पर जेल नियमानुसार केजरीवाल से फोन नंबर भी माना गया है। उसी नंबर पर जेल नियमानुसार केजरीवाल बात कर सकेंगे। पत्नी सुनीता भी हफ्ते में 2 बार 30-30 मिनट तक मिल सकती है। एक ही जेल में होने के बाद भी

केजरीवाल अपने साथियों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन से मुलाकात नहीं कर सकेंगे। कुछ दिन पहले तक जेल नंबर दो में संजय सिंह भी रहे थे। लेकिन अब उन्हें जेल नंबर 5 में शिफ्ट कर दिया गया है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए उनके सेल में 2 लेयर की सुरक्षा रहेगी। उनकी सुरक्षा में क्यूआरटी की टीम को भी लगाया गया है। इस बीच राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान शराब नीति कांड में पहली बार आतिशी के साथ ही मंत्री सौरभ भारद्वाज का नाम भी सामने आया।

गौरतलब है दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में कथित अनियमितता के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले आम आदमी पार्टी के अहम नेता दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं। जब आम आदमी पार्टी के शीर्ष के सभी नेता जेल में हैं, ऐसे में पार्टी और दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी, यह बड़ा सवाल है। एक ऐसे सक्षम नेतृत्व को तलाशने की चुनौती है, जो केजरीवाल की गैरमौजूदगी में पार्टी और दिल्ली में सरकार को संभाल सके। लोकसभा के चुनाव बिल्कुल करीब आ गए हैं, ऐसे में यह चुनौती और बड़ी हो गई है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में पार्टी अपना चुनाव अभियान शुरू करने वाली थी और उसके स्टार प्रचारक केजरीवाल को होना था। कुछ खबरों में कहा गया था कि गिरफ्तारी की आशंका के बीच नेतृत्व को लेकर जिन नामों पर चर्चा चली, उनमें अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, दिल्ली सरकार में मंत्री अतिशी और सौरभ भारद्वाज के नाम शामिल हैं। दिल्ली सरकार में अतिशी पर शिक्षा, वित्त, पीडब्ल्यूडी, राजस्व समेत सबसे अधिक पोर्टफोलियो की जिम्मेदारी है। उन्हें केजरीवाल का खास माना जाता है। इसी तरह सौरभ भारद्वाज भी दिल्ली कैबिनेट के प्रमुख सदस्य हैं और स्वास्थ्य और शहरी विकास जैसे कई महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं। हालांकि अतिशी और सोमनाथ भारती ने पत्रकारों से कहा कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। अतिशी ने कहा कि जरूरत पड़ी तो वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। कोई भी कानून जेल से सरकार चलाने पर प्रतिबंध नहीं लगाता क्योंकि उन्हें कोई सजा नहीं हुई है। केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे।

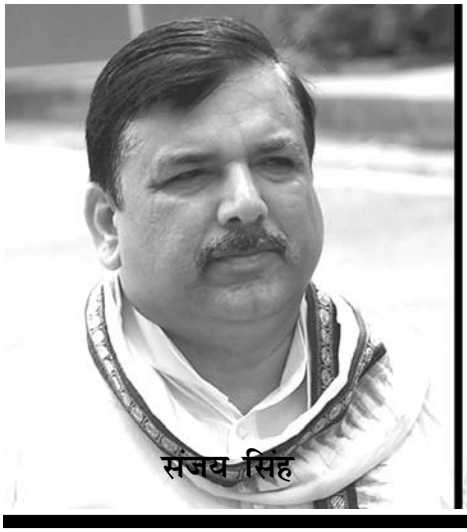
संजय सिंह

सत्येंद्र जैन

हांलाकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के ईडी में फंसने और अब जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी का सारा कामकाज संदीप पाठक संभाल रहे हैं। सवाल है कि आखिर कौन हैं संदीप पाठक। बता दें कि संदीप पाठक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और केजरीवाल के काफी करीबी माने जाते हैं। संदीप पाठक छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के बटहा गांव में पैदा हुए बिलासपुर में उनकी स्कूली पढ़ाई, कैंब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी और आईआईटी दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर, ऑक्सफोर्ड और एमआईटी में रिसर्चर

रहे हैं। उनके 43 रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं, जबकि 490 रिसर्च वर्क में सहायक रहे हैं। संदीप पाठक अप्रैल 2022 से पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रभारी और पंजाब-हिमाचल प्रदेश में आप के सह-प्रभारी हैं। उन्हें राजनीति का काफी अनुभव हैं और अरविंद केजरीवाल की गैर-मौजूदगी में वही कामकाज संभाल रहे हैं। वे अरविंद केजरीवाल के करीबी हैं। बता दें कि संदीप पाठक आम आदमी पार्टी से शुरुआत से ही जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी का 'चाणक्य' माने जाते हैं। वे पंजाब और गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रभारी नियुक्त हुए थे। उनके नेतृत्व में ही पंजाब में आप की सरकार बनी। गुजरात में पार्टी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। उनकी भूमिका को सराहते हुए केजरीवाल ने उन्हें राज्यसभा में सांसद बनाकर भेज दिया। संदीप पाठक के अनुभव और पंजाब में विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कराने में उनकी भूमिका को देखते हुए केजरीवाल ने उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया। वे पार्टी के राजनीतिक मामले देखने वाली समिति के स्थायी सदस्य भी हैं। अब उन पर केजरीवाल की गैर-मौजूदगी में पार्टी, नेताओं, मंत्रियों, विधायकों, वर्करों का मनोबल बनाए रखने की जिम्मेदारी है। उन्होंने हीं पंजाब में बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाया।

बहरहाल, लोकसभा चुनाव सिर पर हैं और ऐसे में विपक्ष की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल को ईडी की हिरासत से छुड़वाने की आप की कोशिशें रंग नहीं ला पाई हैं और कांग्रेस के खिलाफ आयकर विभाग की और कार्रवाई होने की संभावना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और एक निचली अदालत द्वारा दी गई रिमांड को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई चल रही है। लेकिन राजनीतिक रूप से उनकी पार्टी कई समस्याओं से जूझ रही है। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है, जिसका मतलब है वह एक तरह से हिरासत में होते हुए सरकार चला रहे हैं। वही अभी तक हिरासत से उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के लिए दो आदेश भी दिए हैं, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि ईडी इन फैसलों की वैधता की भी जांच कर रही है। केजरीवाल का हिरासत में होना सिर्फ दिल्ली के प्रशासन के नजरिए से ही नहीं बल्कि पार्टी के चुनावी अभियान के नजरिए से भी महत्वपूर्ण है। जिन-जिन राज्यों में पार्टी की चुनावी और राजनीतिक मौजूदगी है, वहां केजरीवाल ही पार्टी का मुख्य चेहरा हैं। इस समय अगर वो हिरासत में नहीं होते तो पार्टी के उम्मीदवारों के लिए कैंपेन कर रहे होते। उनकी गैर-मौजूदगी में पार्टी का स्टार कैंपेनर अभियान से गायब है। इसके अलावा पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी चुनावी अभियान में शामिल होने की जगह प्रदर्शनों में व्यस्त होने पर मजबूर हैं। 'आप' मुसीबतों से घिर जाने वाली अकेली विपक्षी पार्टी नहीं है। कांग्रेस भी एक बड़ी समस्या का सामना कर रही है। हाल ही में आयकर विभाग ने पार्टी का बकाया टैक्स वसूलने के लिए उसके बैंक खातों से 135 करोड़ रुपए ले लिए थे। अब यह संकट और बड़ा होने की संभावना है।

संदीप पाठक

After PM Modi gifted Jill Biden: Lab-grown diamond market gains momentum

After Prime Minister Narendra Modi gifted Jill Biden, US President Joe Biden's wife, the 7.5 carat lab-grown diamond at the White House, the market for these gems have gained momentum, Aukera Jewellery Founder and CEO Lisa Mukhedkar said. "Two years ago, Prime Minister Narendra Modi took 7.5 carat (lab-grown) diamond to the White House (and gifted it to Jill Biden) and that was a demonstration of his belief in this product. And thereafter, the market for these gems have gained momentum. Overall, the government policy has been pro-grown diamonds," she told UNI in a video interview on the sidelines of an event held by her signature Aukera Jewellery.

Mukhedkar said PM Modi supports grown diamonds because they are considered more sustainable and environmentally friendly compared to mined diamonds. "The reason that our Prime Minister is in favour of grown diamond is because it is more sustainable and is more earth friendly choice. That is the reason he is promoting it. My diamonds also are cut and polished in Surat. Nine out of ten diamonds come out of Surat. So, there is employment provided. There is no loss of firegn exchange because it is not imported," she said. Mukhedkar said PM Modi and the central government has been actively endorsing grown diamonds due to their perceived sustainability, economic, and ethical advantages.

"Last year in union budget, the import duty on mine diamond seed has been reduced. So the policy has been very much in favour of grown diamonds and for good reason," she told UNI in a video interview on the sidelines of an event held by her signature Aukera Jewellery. Mukhedkar also implied that grown diamonds are seen as a more ethical choice, potentially referring to concerns over labour practices and environmental impact associated with traditional diamond mining. Lab-grown diamonds are created using a process that involves placing a diamond seed in a reactor and simulating the high temperature and pressure conditions found in the Earth's core. This results in the growth of a rough diamond, which is then cut and polished to produce the final gemstone, Mukhedkar said.

The production of lab-grown diamonds primarily occurs in Surat. Once the initial seed is established, the entire process of growing the diamond and preparing it for sale takes place in India, she said. By producing lab-grown diamonds locally in Surat, and manufacturing jewelry in nearby Mumbai, jewelers can streamline the supply chain and reduce costs. Without the need for importing diamonds, overhead expenses associated with international trade are minimised, Mukhedkar explained. "This enables jewelers to offer their products at fair prices to consumers. Additionally, with the jewellery being manufactured domestically, it can easily be distributed to various parts of the country, further optimizing logistics and potentially reducing delivery times for customers," she said.

Indeed, lab-grown diamonds have been around for several decades, but their acceptance and recognition as genuine diamonds in the market have evolved over time. In 2018 when the US Federal Trade Commission (FTC) officially recognised lab-grown diamonds as diamonds, it had a profound impact on the market, Mukhedkar said. Before this acknowledgment by the FTC, lab-grown diamonds may not have received the same level of recognition or legitimacy in the jewelry industry. However, once the FTC confirmed their status as diamonds, it provided clarity and assurance to consumers, jewelers, and other stakeholders, leading to increased acceptance and demand for lab-grown diamonds, Mukhedkar said.

SC directs SBI to submit all conceivable details of electoral bonds by March 21

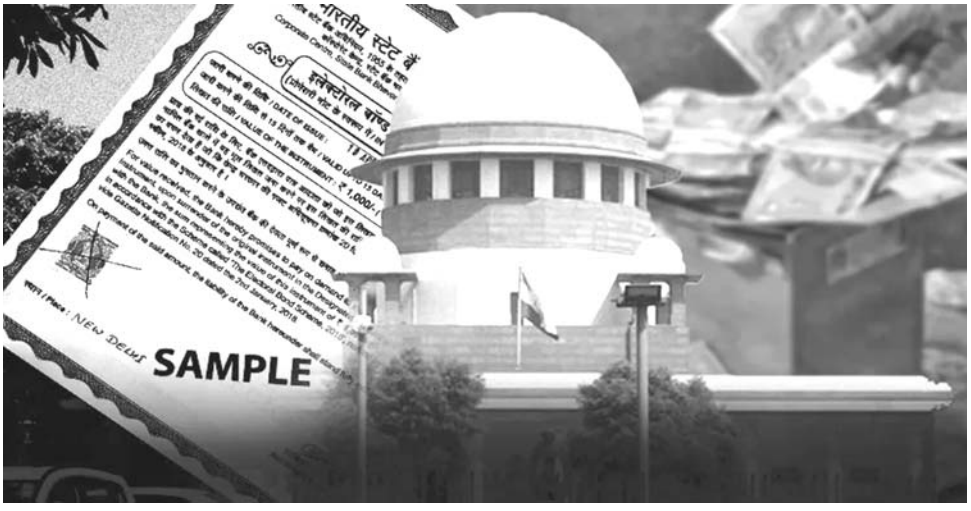

The Supreme Court on Monday asked the State Bank of India (SBI) to disclose all 'conceivable' details available with it regarding electoral bonds, including the alphanumerical number and serial number, for any of the bonds purchased.

A bench headed by Chief Justice DY Chandrachud said that to avoid any controversy in the future, the chairperson of the bank should file an affidavit by 5 PM on Thursday stating that it has disclosed all details in its custody and that no details have been withheld." The court directed. The Court stated that its February 15 judgment mandated the SBI to disclose "all details," including the date of purchase or redemption, the name of the purchaser or recipient, and the denomination. The use of the word "including" means that the details specified in the judgment are illustrative and not exhaustive.

The Court had further directed that the Election Commission of India upload on its website the details received from the SBI forthwith upon their receipt. Last week, the same Constitutional Bench, comprising Chief Justice DY Chandrachud and Justices Sanjiv Khanna, BR Gavai, JB Pardiwala, and Manoj Misra, heard the plea of the Election Commission, which sought to return the sealed documents containing details of electoral bonds furnished earlier to the court as they had not retained any copies of the said documents. During last week's hearing, the five-judge bench stressed the need for the State Bank of India (SBI) to disclose the alphanumeric number corresponding to each electoral bond, along with the details it has already disclosed regarding the purchase and redemption of the bonds. Accordingly, the Apex Court issued notice to the SBI and directed the matter to be posted for hearing on Monday, March 18.

The CJI said, “In the judgment, we had specifically asked the State Bank of India to disclose 'all details.' That includes the bond numbers as well. The bank cannot be selective in disclosing all details. Do not wait for the orders of this court.” Senior Advocate Harish Salve, appearing for the State Bank of India, said, “If the numbers are to be given, we will give them. That's no problem.” He defended the bank by saying that the current status of the disclosure was based on its understanding of the court's interim directive in April 2019. To this end, the chief justice reiterated, “When we say, 'all details,' it includes all conceivable data. This interim order has merged with our final judgment. We will clarify that and say that the State Bank of India will not only file the bond numbers but also ask it to submit an affidavit saying that it has not suppressed any details. The onus should not be on the court." Senior Advocate Mukul Rohatgi, representing FICCI and ASSOCHAM, tried to convince the court that the disclosure of the bond numbers should be deferred.

To this, Chief Justice DY Chandrachud responded, “We have no such application on board.” When Rohatgi sought to press his application on behalf of industrialists, he questioned how the information could be asked to be disclosed when there was a guarantee of anonymity. To this, Chief Justice Chandrachud replied, "Mr. Rohatgi, there is only one answer. With effect from April 12, 2019, we directed the collection of details. Everyone was put on notice at the time. This is why we did not ask for the disclosure of the bonds sold prior to this interim order, as the CJI clarified.

आम चुनाव किसके - कितने खास

● **अमित कुमार**

18 वीं लोकसभा चुनाव का विगुल बज चुका है और लोकसभा सदन की 543 सीटों पर 2024 में आम चुनाव कुल सात चरणों में कराये जायेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल से शुरू होगी और आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा। इसके बाद 4 जून को सभी चरणों की एक साथ मतगणना होगी एवं इसी दिन नतीजे जारी हो जाएंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक बिहार में पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। इसके बाद 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। तीसरे चरण के लिए 7 मई, चौथे चरण के लिए 13 मई, पांचवें चरण के लिए 20 मई, छठे चरण के लिए 25 मई और सातवें एवं आखिरी चरण के लिए 1 जून को वोट पड़ेंगे। सनद् रहे कि 18वीं लोकसभा चुनाव की

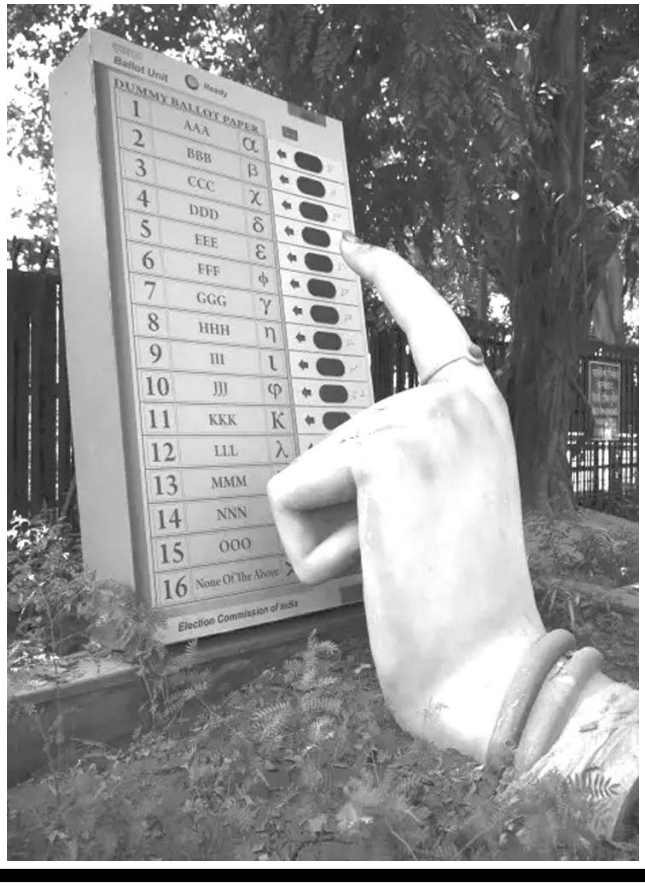

तैयारियों को लेकर हर वह छोटे-बड़े दल अपनी जोर आजमाइस लगाते दिखने लगे हैं। रैलियां शुरू हो चुकी है। जनता के बीच विकास के कार्यों से लेकर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुख्य मुद्दों को खूब परोसा जा रहा है। दिगर बात है कि एक तरफ क्षेत्रीय पार्टियां मजबूती से अपने सीट से खड़े उम्मीदवारों को लेकर राजनीतिक रास्ता अख्तियार करने में जुटी है तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय पार्टियां पीएम के पद के लिए कुर्सी-कुर्सी खेल रही है। मुख्य रूप से राष्ट्रीय पटल पर भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में केंद्र की कुर्सी पर विराजमान है तो वही कांग्रेस है जो उस कुर्सी से पीएम मोदी को पटखनी देने में कोई कोर-कसर छोड़ने को तैयार नहीं। लोकसभा के इस युद्ध में कांग्रेस नित इंडिया गठबंधन को साथ लेकर सभी विपक्षी दलों को एक साथ एक मंच पर लाकर केंद्र की मोदी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए जिस प्रकार मेहनत करते दिख रही है, उससे अंदाजा लगाया

जा सकता है कि इस बार का होने वाला लोकसभा चुनाव नये प्रयोग के साथ दिलचस्प होगा। भाजपा 'मोदी की गारंटी' की नैया पर '400 के पार' का नारा दे रही है।

बहरहाल, कोई भी चुनाव लड़ने में जितने पैसे खर्च किये जाते हैं, उनमें तो जनता के लिए कई लाभकारी योजना चालू हो जाये। देखा जाए तो अगर किसी की चुनाव लड़ने की इच्छा हो और उसके पास इतनी संपत्ति और बैंक डिपॉजिट हो तो वह यह खर्च उठा कर चुनाव लड़ सकता है, लेकिन हकीकत इससे काफी दूर है। अमेरिकी पत्रिका 'द इकोनॉमिस्ट' की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव दुनिया के सबसे महंगे चुनाव हो सकते हैं। अमेरिकी चुनावों से भी ज्यादा महंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक इन लोकसभा चुनावों में कम से कम 10 अरब डॉलर, यानी करीब 83 हजार करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं। इसका मतलब है 543 सीटों के हिसाब से औसतन हर सीट के लिए कम से कम 153 करोड़ रुपये। इससे पहले एक भारतीय निजी संस्थान ने 2019 के लोकसभा चुनावों में हुए खर्च का अनुमान लगाया था। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के मुताबिक 2019 में कुल 55-60,000 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, यानी करीब 100 करोड़ प्रति सीट। अगर हर सीट पर 10 गंभीर प्रत्याशी भी हों, तो हर प्रत्याशी को कम से कम 10 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े होंगे।

गौरतलब है कि देश में लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बजने के साथ ही चुनाव मैदान में जहां कई ऐसे प्रखर वक्ता दिखेंगे जो वाक् कौशल से सबका ध्यान खीचेंगे तो अनेक पर्दे के पीछे रहकर रणनीति तैयार कर पार्टी की जीत का खाका तैयार करेंगे। इन प्रमुख नेताओं और रणनीतिकारों पर सबका ध्यान केंद्रित रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से लेकर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी उन 10 प्रमुख राजनीतिक हस्तियों में शामिल हैं, जो किसी न किसी स्तर पर चुनावी विमर्श तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। शुरूआत देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से करते हैं, जिन्होंने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए प्रयासरत प्रधानमंत्री मोदी न केवल भारत पर अपने चुनावी प्रभुत्व की मुहर लगाना चाहते हैं, बल्कि पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए लगातार एक और जीत के साथ इतिहास रचने की कोशिश में हैं। प्रधानमंत्री मोदी 'मोदी की गारंटी' और 'विकसित भारत' के ईद-गिर्द चुनावी विमर्श को खड़ा करने की कोशिश करेंगे। 73 वर्षीय मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के आत्मविश्वास के साथ चुनाव में उतर रहे हैं और उन्होंने अपने अगले कार्यकाल के लिए खाका पर काम भी शुरू कर दिया है। वही केंद्रीय मंत्रिमंडल में अघोषित नंबर 2 और भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह एक बार फिर अपनी पार्टी की रणनीति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। चाहे अनुच्छेद 370 को निरस्त करना हो या संशोधित नागरिकता कानून (सीएए), उन्होंने गृहमंत्री के रूप में कई मुश्किल परिस्थितियों में सरकार को संभाला है। 59 वर्षीय अमित शाह एक बार फिर चुनावी युद्ध के मैदान में अपने सैनिकों का नेतृत्व करते हुए एक सेनापति के अवतार में नजर आएंगे। अब बात राहुल गांधी की करें तो कांग्रेस अपने पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को पार्टी के लिए 'वैचारिक धुरी' कहती है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 'भारत जोड़ो यात्रा' ने उनकी छवि में बदलाव किया, लेकिन राज्यों के विधानसभा चुनावों में हार ने इस पर सवालिया निशान लगा दिया है कि उनकी यात्रा कितनी प्रभावी थी। अपनी 'भारत जोड़ो

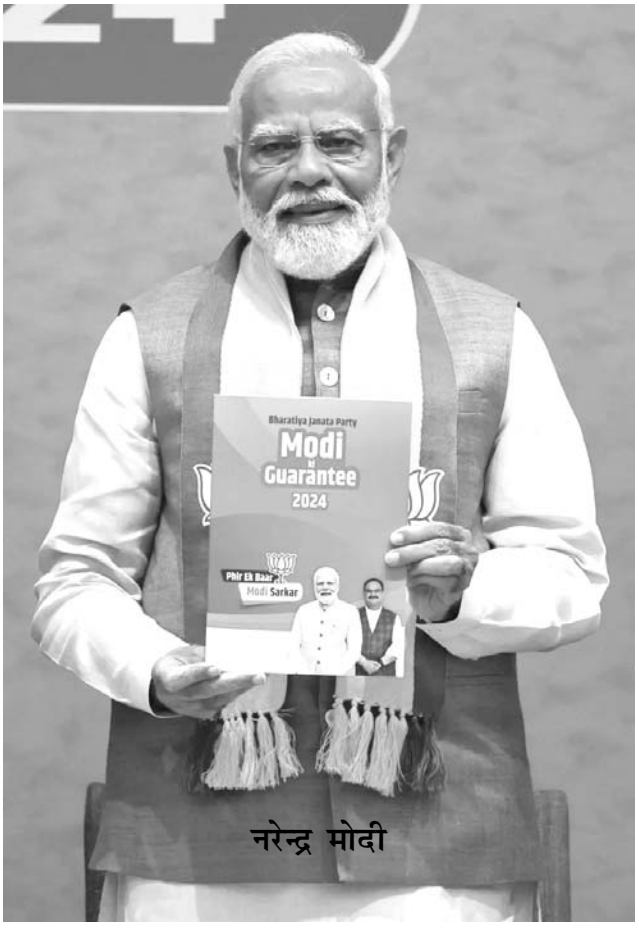

नरेन्द्र मोदी

राहुल गांधी

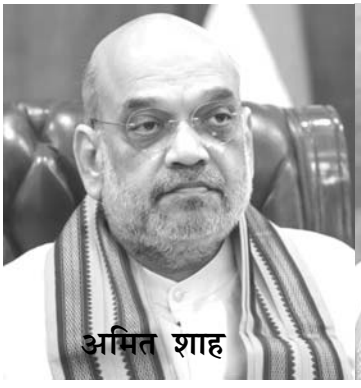
अमित शाह

मल्लिकार्जुन खरगे

ममता बनर्जी

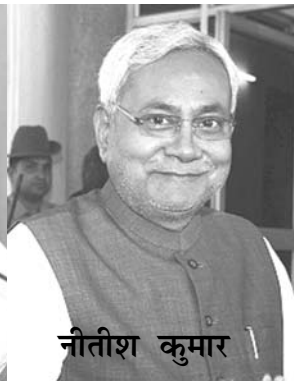
नीतीश कुमार

न्याय यात्रा' के साथ, 53 वर्षीय गांधी फिर से लोगों के लिए 'न्याय' सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनता के बीच हैं। यह लोगों को पसंद आएगा या नहीं, यह सिर्फ समय ही बताएगा। वही कांग्रेस के कार्यकर्ता से शुरुआत कर अध्यक्ष पद तक पहुंचे मल्लिकार्जुन खरगे सक्रिय राजनीति में 5 दशक का अनुभव रखते हैं। उन्होंने अक्टूबर, 2022 में पार्टी की कमान संभाली। 81 वर्षीय खरगे को अब कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए अपनी सबसे कड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ रहा है। अब बात तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी की करते हैं, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। लेकिन इससे पहले विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के साथ प्रदेश में उनकी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर ऊहापोह की स्थित लंबे समय तक बनी रही। 69 वर्षीय बनर्जी पश्चिम बंगाल में भाजपा को कड़ी टक्कर देती हैं और भाजपा के साथ द्वंद्व में उलझी हुई हैं। भाजपा ने संदेशखाली मामले को लेकर उन पर हमले तेज कर दिए हैं। जब विपक्षी दलों के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन की बात आती है तो ममता बनर्जी का मंत्र 'एकला चलो' का होता है, लेकिन वह भाजपा के विरोध में वैचारिक मुद्दे पर दृढ़ दिखती हैं। दूसरी तरफ बिहार की सत्ता में बने रहने और आसानी से राजनीतिक गठबंधन बदलने के अपने कौशल के लिए जाने जाने वाले नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर पाला बदला है। 73 वर्षीय नेता का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में जाना, 'इंडिया' गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। उनके भाजपा के साथ हाथ मिलाने से बिहार में नाटकीय रूप से स्थिति बदल गई है। अब लोगों को उनके नवीनतम 'पाला बदलने' पर निर्णय देना है। दूसरी तरफ शरद पवार भारतीय राजनीति के दिग्गजों में शुमार किए जाते हैं। अपने ही भतीजे अजित पवार से परेशान और धोखा खाने वाले 83 वर्षीय मराठा नेता शायद अपने करियर के आखिरी पड़ाव में सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी हार न मानने वाले रवैये के लिए पहचाने जाने वाले पवार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के लिए मुश्किल साबित हो सकते हैं। उनकी पहल पर ही महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी अस्तित्व में आया। बात अगर एमके स्टालिन की करें तो द्रमुक सुप्रीमो ने तमिलनाडु में अपना प्रभुत्व स्थापित किया है और दक्षिणी राज्य में भाजपा के खिलाफ विपक्ष की बड़ी ताकत हैं। स्टालिन से तमिलनाडु में विपक्षी गठबंधन को महत्वपूर्ण चुनावी बढ़त दिलाने की उम्मीद है। 71 वर्षीय स्टालिन गांधी परिवार के कट्टर समर्थक हैं, लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं की 'सनातन धर्म' पर विवादास्पद टिप्पणियों ने कई मौकों पर 'इंडिया' गठबंधन को बैकफुट पर ला दिया और उत्तर में उन्हें नुकसान हो सकता है। अब युवा और उभरते नेता तेजस्वी यादव की बात करें तो राजद नेता फिर से बिहार में विपक्ष में हैं, लेकिन 'इंडिया' गठबंधन में उनका कद बढ़ गया है। 34 वर्षीय यादव ने बिहार में विपक्षी समूह का उत्साहपूर्वक नेतृत्व किया है और कई लोग उन्हें बिहार में उनके पिता लालू प्रसाद की विरासत के सक्षम उत्तराधिकारी के रूप में देखते हैं। वह राजग के गणित को बिगाड़ पाएंगे या नहीं, इसका इम्तिहान लोकसभा चुनाव में होगा। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन औवेसी ने अक्सर विधानसभा चुनावों में विपक्षी गठबंधन के लिए 'खेल बिगाड़ने' की भूमिका निभाई है और कुछ नेताओं ने उन्हें भाजपा की 'बी-टीम' करार दिया है। 54 वर्षीय ओवैसी तेलंगाना के अलावा देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी पार्टी के बढ़ने और चुनाव लड़ने के अधिकार को लेकर दृढ़ रहे हैं। क्या वह विपक्षी दलों या भाजपा का गणित बिगाड़ देंगे, यह देखना भी दिलचस्प रहेगा।

बहरहाल, देश की राजनीति में सक्रिय ये दस ऐसे नेता जो लोकसभा चुनाव में अपनी भूमिका राष्ट्रीय पटल पर जनता के बीच कितने निखार पातें हैं, ये तो वक्त बतायेगा किन्तु लोकसभा 2024 के चुनाव में कौन दिग्गज मैदान में किश्मत आजमायेगा या रण को यू ही छोड़ देगा पर चर्चा जोरो पर है। ऐसे में एक नाम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का आ रहा है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि

शरद पवार

एम के स्टालिन

तेजस्वी यादव

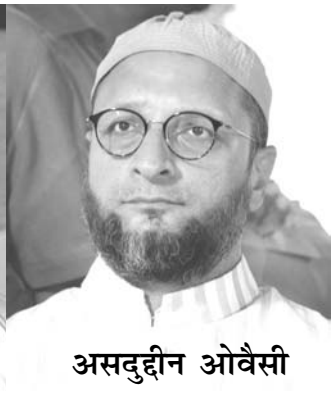
असदुद्दीन ओवैसी

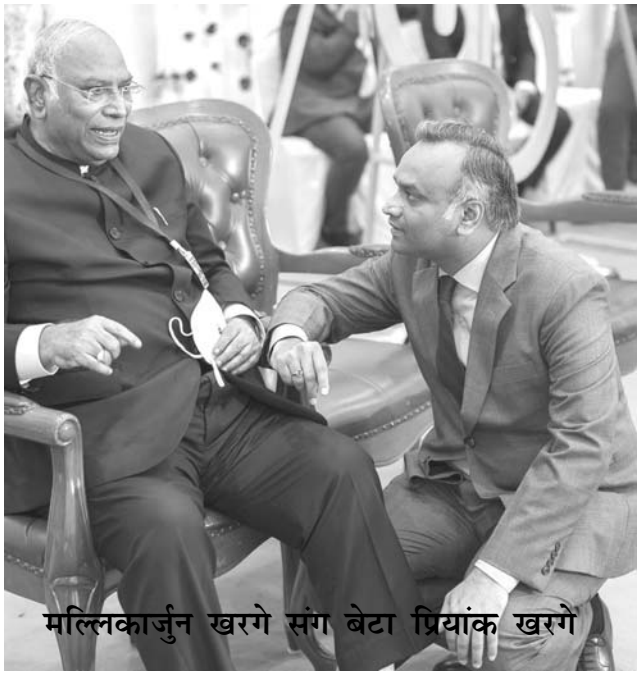
मल्लिकार्जुन खरगे संग बेटा प्रियांक खरगे

राधाकृष्ण डोडामणी

वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते। इतना ही नहीं कांग्रेस के ज्यादातर दिग्गज नेता लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उनमें कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी शामिल हैं। खरगे इस समय राज्यसभा से सांसद हैं और उनका कार्यकाल भी 4 साल का बाकी है, इसीलिए वे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते। इनके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते। खरगे के लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने के पीछे एक से ज्यादा कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि खरगे गुलबर्गा से 2019 में लोकसभा चुनाव हार गए थे। तब खरगे को भाजपा के डॉ. उमेश जाधव ने 95 हजार से ज्यादा वोटों से हराया था। ऐसे में खरगे कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि इस समय वे पार्टी के अध्यक्ष हैं और यदि फिर चुनाव हारते हैं तो न सिर्फ उनकी बल्कि पार्टी की भी किरकिरी होगी। वही यह भी कहा जा रहा है कि खरगे गुलबर्गा सीट पर इसलिए चुनाव नहीं लड़ना चाहते क्योंकि वे इस सीट पर अपने दामाद को लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहते हैं। इसके साथ ही उनके बेटे प्रियांक खरगे कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार में मंत्री हैं। चुनाव नहीं लड़ने के पीछे खरगे का अपना तर्क है। उनका मानना है कि वे एक निर्वाचन क्षेत्र तक सीमित नहीं रहना चाहते। पार्टी अध्यक्ष के नाते लोकसभा चुनाव में वे पूरे देश पर ध्यान केन्द्रित करना चाहते हैं। वही खरगे ही नहीं दूसरे बड़े नेता भी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी लोकसभा चुनाव लड़ने से इंकार कर चुके हैं। उनका कहना है कि वे अपने गढ़ छिंदवाड़ा को नहीं छोड़ना चाहते। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर उनके बेटे नकुल नाथ सांसद हैं। नकुल का टिकट लगभग तय है। राजस्थान में भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। वे भी अपने बेटे वैभव गहलोत को सेट करना चाहता है। वैभव का जालौर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। टोंक सीट से विधानसभा चुनाव जीतने वाले कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने में अरुचि दिखाई है।

कमलनाथ और उनका बेटा नकुल नाथ

गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी दलों ने अपनी-अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी अलग-अलग राज्यों में सौगात देना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर विपक्षी दलों ने भी मोदी को घेरने के लिए अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। एक वक्त जो इंडिया गठबंधन पूरी तरह बिखरता दिख रहा था, अब उसके तार फिर से जुड़ना शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है, वहीं दिल्ली, हरियाणा, गोवा और गुजरात में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों को लेकर सहमति बन गई है। हालांकि पंजाब में दोनों ही पार्टियां अलग-अलग चुनाव लड़ने जा रही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी या भाजपा के

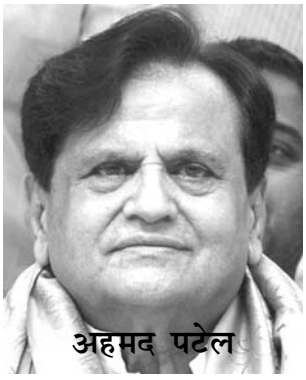
अहमद पटेल

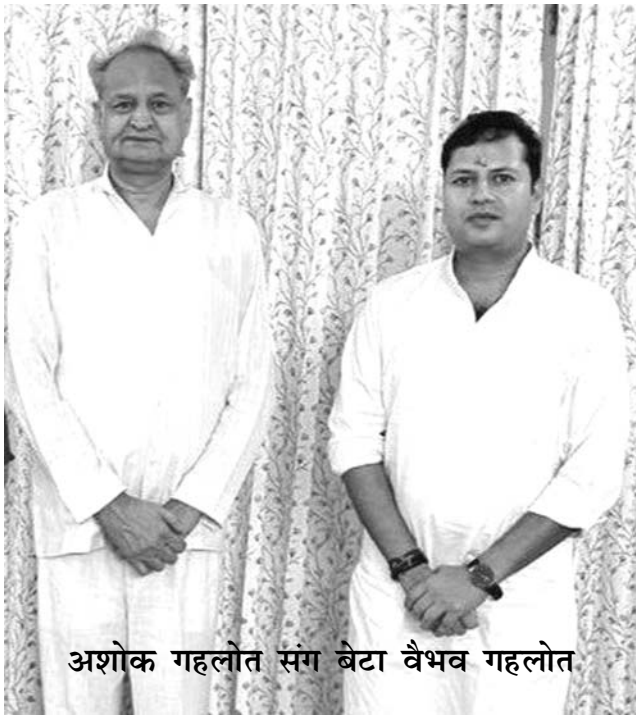
अशोक गहलोत संग बेटा वैभव गहलोत

मुमताज पटेल

विजय रथ आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्ष के लिए लगभग असंभव है। लेकिन, पिछले लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीतने वाली भाजपा ने इस बार 370 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जबकि गठबंधन को मिलाकर 400 से ज्यादा सीटें जीतने का टारगेट है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन में सहमति बनते हुए दिख रही है, भाजपा के लिए यह लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं होगा। लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतने का रिकॉर्ड राजीव गांधी के नाम है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस ने 404 लोकसभा सीटें जीती थीं। वही चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मानें तो भाजपा के 370 सीट तक पहुंचने की संभावना नहीं है। हालांकि वह पश्चिम बंगाल में इस बार भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। लोगों को भी इस 370 के लक्ष्य को सच नहीं मानना चाहिए। उनके मुताबिक, 2014 के बाद 8-9 चुनाव ऐसे हुए जहां भाजपा अपने तय लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई। मैं कह सकता हूं कि भाजपा अकेले 370 सीट हासिल नहीं कर सकती। इसकी संभावना करीब-करीब जीरो ही मानता हूं। हालांकि उनका मानना है कि संदेशखाली मामले के बाद बंगाल में भाजपा की लोकसभा सीटें बढ़ सकती हैं। वही आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस से हाथ मिला लिया है। दिल्ली, हरियाणा, गोवा और गुजरात में उनके बीच सीटों को लेकर सहमति बन गई है। दिल्ली में वर्तमान में सातों सीटों पर भाजपा का कब्जा है, लेकिन राहुल और केजरीवाल के साथ आने से मुकाबला रोचक होने की पूरी उम्मीद है। विधानसभा चुनाव में आप ने दिल्ली की 70 में से 62 सीटें जीती थीं। ऐसे में उन्हें पूरी तरह कमजोर आंकना गलत होगा। गुजरात के अलावा राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं, जहां 2019 में भाजपा ने सभी लोकसभा सीटें जीती थीं। हालांकि गुजरात में भले ही आप और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है, लेकिन गुजरात में दोनों ही पार्टियों के लिए करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। भरूच सीट को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे स्व० अहमद पटेल के परिजनों ने बागी तेवर अपना लिए हैं। 2019 में भी भाजपा ने सभी 26 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार भी लोकसभा चुनाव में भाजपा का ही पलड़ा भारी रहने की पूरी संभावना है। हरियाणा में गठबंधन कुछ सीटें जीत सकता है। किसानों की नाराजगी का फायदा उसे मिल सकता है। पंजाब में भी नाराज किसान कांग्रेस और आप का समर्थन कर सकते हैं। हालांकि पंजाब में वर्तमान में भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन लोकसभा चुनाव का परिदृश्य विधानसभा से अलग होगा। ऐसे में यह कहना मुश्किल होगा कि आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव जैसा प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में भी कर पाए। यहां कांग्रेस और आप अलग-अलग चुनाव लड़ेंगी, जबकि भाजपा और शिरोमणि दल साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इसका फायदा उन्हें मिल सकता है। पिछले चुनाव में पंजाब की 13 में से 8 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, जबकि भाजपा और शिरोमणि अकाली दल ने 2-2 सीटें जीती थीं। आप सिर्फ एक सीट ही जीत पाई थी। पंजाब में कांग्रेस के लिए इसलिए भी मुश्किल होने वाली है क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ जैसे लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। वही दक्षिण के राज्यों-कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में लोकसभा की कुल 129 सीटें हैं। केरल और तमिलनाडु मे भाजपा का कोई जनाधार नहीं है, जबकि कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में वह कुछ सीटें जीत सकती है। कर्नाटक

प्रशांत किशोर

अरविंद केजरीवाल

भगवंत मान

कैप्टन अमरिंदर सिंह

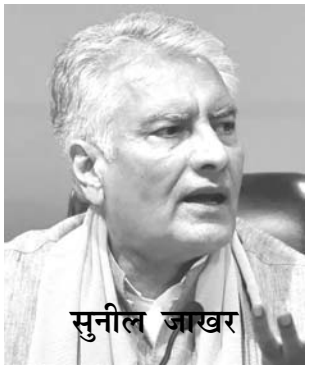
सुनील जाखर

नरेन्द्र मोदी

अजय राय

में भाजपा का सबसे ज्यादा प्रभाव है। यहां भाजपा की सरकार भी रह चुकी है। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। सबसे ज्यादा 39 सीटें तमिलनाडु में हैं, जहां कांग्रेस का सत्तारूढ़ डीएमके के साथ गठबंधन है। आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्षी दल भाजपा को चुनौती देते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती खुद को मजबूत बनाए रखना होगी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को तीसरे कार्यकाल के लिए रोकना फिलहाल तो विपक्ष के लिए मुमकिन दिखाई नहीं देता।

बहरहाल, आगामी लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ से अधिक मतदाता 7 चरणों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने कहा कि मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में 15.34 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 8. 17 करोड़ पुरुष और 7. 17 करोड़ महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा 6,638 तृतीय लिंग (ट्रांसजेंडर) मतदाता और 12.51 लाख से अधिक दिव्यांग मतदाता भी हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य में 1.62 लाख से अधिक मतदान केन्द्र हैं। बताते चले कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा और उसकी सहयोगी अपना दल (सोनेलाल) के गठबंधन ने समाजवादी पार्टी (सपा), बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के महागठबंधन के अंकगणित को गलत साबित करते हुए 80 लोकसभा सीटों में से 64 पर जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस ने एकमात्र लोकसभा सीट रायबरेली पर जीत हासिल की थी। महागठबंधन में बसपा को 10 तो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने पांच सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं रालोद चुनाव में अपना खाता भी नहीं खोल सकी थी। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में इस बार भाजपा की सीटें कम हो सकती हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ आने से ये दोनों ही पार्टियां पिछली बार के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। भाजपा ने 2019 के चुनाव में 80 में से 62 लोकसभा सीट जीती थीं, जबकि गठबंधन को मिलाकर 64 सीटों पर कब्जा किया था। वहीं समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीतकर तीसरे स्थान पर रही थी। कांग्रेस 1 सीट पर ही सिमट गई थी। वही कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी अमेठी जैसी परंपरागत सीट को भी नहीं बचा पाए थे। इस बार सबसे ज्यादा नुकसान मायावती की बसपा को होता दिखाई दे रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी यह पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई थी।

आदित्य यादव

हो सकता है कि बसपा अपना पिछला प्रदर्शन भी न दोहरा पाए। पिछली बार बसपा ने 10 लोकसभा सीटें जीती थीं। राम मंदिर जैसे मुद्दे के बावजूद भाजपा के लिए पिछला प्रदर्शन दोहराने की बड़ी चुनौती होगी। वैसे हिन्दी पट्टी में इस बार भी भाजपा का जोर रहेगा। दूसरी तरफ बाबा विश्वनाथ की नगरी और उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित लोकसभा सीट वाराणसी (काशी या बनारस भी) सीट पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक बार फिर चुनाव मैदान में हैं। वे 2014 और 2019 में इस सीट से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई भी नाम सामने नहीं आया है। माना जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को एक बार फिर मोदी के खिलाफ उतारा जा सकता है। कांग्रेस और सपा के बीच समझौते के तहत इस बार इस सीट पर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार नहीं रहेगा। पिछली बार यानी 2019 में सपा ने शालिनी यादव को मोदी के सामने उतारा था। यह चुनाव मोदी ने 4 लाख 79 हजार वोटों से जीता था। शालिनी को 1 लाख 95 हजार वोट मिले थे। कांग्रेस के अजय राय 1 लाख 52 हजार वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। ऐसी अटकलें हैं कि कांग्रेस मोदी के खिलाफ एक बार फिर अजय राय को मैदान में उतार सकती है। हालांकि अजय राय 2009, 2014 और 2019 में तीसरे स्थान पर रहे थे। 2009 में वे समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन तब भी तीसरे स्थान पर ही रहे थे। 2014 और 2019 में अजय राय तीसरे स्थान पर रहे थे। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ही एकमात्र ऐसे उम्मीदवार रहे हैं, जो 2 लाख से ज्यादा वोट हासिल कर पाए हैं। अन्यथा इस सीट पर हारने वाले सभी उम्मीदवार 2 लाख के नीचे ही वोट हासिल कर पाए हैं। इस चुनाव में मोदी 3 लाख 71 हजार से भी ज्यादा वोटों से जीते थे। वही अजय राय की गिनती

यूपी भाजपा का बाहुबली नेता के रूप में होती है। उनकी राजनीति की शुरुआत भाजपा की विद्यार्थी शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हुई। वे 1996 से 2007 के बीच भाजपा के टिकट पर लगातार तीन बार कोलासला निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। यह वाराणसी जिले में आती है। लोकसभा टिकट नहीं मिलने के बाद राय ने भाजपा छोड़ दी। इसके बाद वह सपा में शामिल हो गए और 2009 के लोकसभा चुनाव में मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ चुनाव हार गए। 2009 में उन्होंने कोलासला निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा उपचुनाव लड़ा और जीते भी। राय 2012 में भाजपा में शामिल हो गए। नए परिसीमन के बाद कोलासला निर्वाचन क्षेत्र का अस्तित्व समाप्त हो गया। 2012 के विधानसभा चुनाव में नवनिर्मित पिंडरा निर्वाचन क्षेत्र से उन्होंने जीत हासिल की। इस क्षेत्र में पूर्व कोलासला निर्वाचन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय 2 बार मोदी के खिलाफ चुनाव हार चुके हैं, लेकिन कुछ पूर्व उन्होंने कहा कि इस बार काशी में मोदी को जमीन दिखा देंगे। हालांकि मोदी के खिलाफ राय का लोकसभा चुनाव जीतना लगभग असंभव है, लेकिन उन्हें सपा का समर्थन मिलने की स्थिति में मुकाबला रोचक होने की उम्मीद है। वही दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल को बदायूं से उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। वर्तमान में यह सीट भाजपा के पास है, जहां पिछली बार संघमित्रा मौर्य ने अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेन्द्र यादव को 18000 से ज्यादा वोटों से हराया था। हालांकि धर्मेन्द्र ने 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में

स्वामी प्रसाद मौर्य

इस सीट पर जीत हासिल की थी। इस बार भाजपा से वर्तमान सांसद संघमित्रा मौर्य का टिकट कटना तय माना जा रहा है। क्योंकि उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा छोड़कर पहले सपा में चले गए थे, अब उन्होंने राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के नाम से नए दल का गठन कर लिया है। बताते चले कि बदायूं सीट पर 1996 से 2014 तक लगातार समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, लेकिन 2019 में उसके दिग्गज नेता धर्मेन्द्र यादव भाजपा की संघमित्रा मौर्य से चुनाव हार गए थे। इस बार भी सपा ने पहली सूची में बदायूं से धर्मेन्द्र को ही उतारा था, लेकिन तीसरी सूची आते-आते उनके स्थान पर अखिलेश और धर्मेन्द्र के चाचा शिवपाल को उम्मीदवार बना दिया गया। 2014 के चुनाव में धर्मेन्द्र यादव ने भाजपा के वागीश पाठक को 1 लाख 66 हजार वोटों के बड़े अंतर से हराया था। 2019 में कांग्रेस के सलीम शेरवानी करीब 52 हजार वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे थे, लेकिन इस बार कांग्रेस और सपा का गठजोड़ हो गया है। इसलिए भी शिवपाल यादव का दावा मजबूत माना जा रहा है। उम्मीदवारी पहले घोषित होने से शिवपाल को चुनाव प्रचार और अपनी रणनीति बनाने के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा। हालांकि शिवपाल सिंह यादव बदायूं से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। वे इस सीट पर अपने बेटे आदित्य यादव को उम्मीदवारी चाहते हैं। फिलहाल इसी सीट पर सपा प्रत्याशी को लेकर संशय बरकरार है। शिवपाल से जब संवाददाताओं ने पूछा कि क्या बदायूं से वह चुनाव लड़ेंगे या फिर उनके बेटे आदित्य मैदान में उतरेंगे? इस पर उन्होंने कहा कि जहां भी हम गए हैं, बैठक की है, सम्मेलन किए हैं तो जनता ने मांग की है कि उन्हें युवा उम्मीदवार चाहिए। इस सवाल पर कि आदित्य को उम्मीदवार बनाने की बात पर कब तक मोहर लग सकती है? शिवपाल ने कहा कि अभी जो समाजवादी पार्टी की सूची जारी हुई है उसमें किसका नाम है? हमारा नाम है। मांग की गई है, मांग तो कोई भी कर सकता है। सूची तो राष्ट्रीय नेतृत्व ही जारी करेगा। उसने जारी की है। उन्होंने आदित्य के चुनाव लड़ने की सम्भावनाओं के बारे में पूछे गये सवाल पर कहा कि कुछ रणनीति के हिस्से होते हैं। अब वह रणनीति आपको तो नहीं बताई जाएगी। रणनीति को रणनीति ही रहने दीजिए। हम लड़ेंगे भी, लड़ाएंगे भी। आप चिंता ना करें। उल्लेखनीय है कि बदायूं में हुए सपा कार्यकर्ता सम्मेलन में इस लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए जाने के लिए आदित्य यादव का नाम प्रस्तावित किया गया है। यह प्रस्ताव अब सपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के पास भेजा जाएगा। भाजपा के 400 सीटें जीतने के दावे के बारे में शिवपाल ने कहा कि पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी भाजपा को हरा रही है। सपा अपनी सीटें जीतेगी। भाजपा सत्ता में नहीं आ पाएगी।

डिम्पल यादव

वही दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। सपा ने इस सीट पर अखिलेश यादव की पत्नी और मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया है। किसी समय यह सीट मैनपुरी जिला पूर्व के नाम से जाती जाती थी। इस सीट पर 28 साल यानी 1996 से सपा का ही कब्जा है। वर्तमान में डिंपल यादव यहां से सांसद हैं। भले ही भाजपा यूपी में सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है, लेकिन इस सीट को सपा से छीनना भाजपा के लिए लगभग नामुमकिन है। क्योंकि भाजपा यहां से एक बार भी चुनाव नहीं जीत पाई है। 1952 में पहली बार यहां से कांग्रेस के बादशाह गुप्ता चुनाव जीते थे। कांग्रेस इस सीट पर 5 बार चुनाव जीत चुकी है, जबकि 1977 और 1980 में इस सीट पर रघुनाथ सिंह वर्मा ने जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में विजय हासिल की थी। 1989 से 1996 तक यहां जनता दल के टिकट पर उदय प्रताप सिंह चुनाव जीते थे। 1996 में इस सीट पर पहली बार मुलायम सिंह यादव ने जीत हासिल की थी। तब से इस सीट पर समाजवादी पार्टी का ही कब्जा है। वर्तमान में इस सीट से मुलायम की बहू डिंपल यादव सांसद

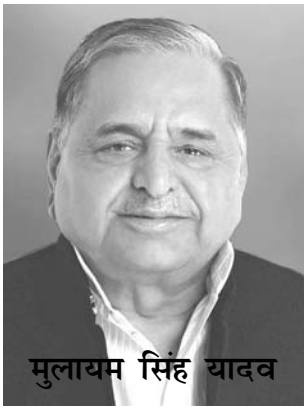
मुलायम सिंह यादव

हैं। मुलायम के निधन के कारण खाली हुई इस सीट पर डिंपल यादव ने 2 लाख 88 हजार वोटों से बड़ी जीत हासिल की थी। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में मुलायम यहां से 95 हजार वोटों से जीते थे। 2014 में मोदी लहर के बावजूद मुलायम सिंह ने शत्रुघ्न सिंह चौहान को 3 लाख 64 हजार 666 वोटों से हराया था। डिंपल यादव कन्नौज से भी 2 बार लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं। एक बार के उपचुनाव में डिंपल कन्नौज से लोकसभा के लिए निर्विरोध चुनी गईं। आजादी के बाद डिंपल ऐसी चौथी नेता रहीं जो यूपी से निर्विरोध लोकसभा पहुंचीं। हालांकि डिंपल यादव को दो बार लोकसभा चुनाव में हार का स्वाद भी चखना पड़ा। बता दें कि मैनपुरी सीट का जातिगत गणित भी डिंपल यादव के पक्ष में ही है। यहां 3.5 लाख के लगभग यादव मतदाता हैं। इनमें बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के ही खाते में जाता है। यहां डेढ़ लाख के लगभग ठाकुर वोटर्स हैं, जबकि 1 लाख 60 हजार शाक्य मतदाता हैं। जबकि 1 लाख के लगभग वैश्य और मुस्लिम मतदाता हैं। यहां 20 हजार ब्राह्मण तथा जाटव मतदाता 1 लाख 40 हजार के आसपास हैं। लोकसभा चुनाव में पलड़ा सपा का ही भारी रहने की संभावना है। इस लोकसभा सीट के अंतर्गत पांच विधानसभा सीटें आती हैं। करहल से अखिलेश यादव विधायक हैं, जबकि जसवंत नगर से उनके चाचा शिवपाल यादव विधायक हैं। किशनी सीट भी सपा के पास ही है, जबकि मैनपुरी और भोगांव सीट भाजपा के पास हैं।

Spiritual leader Sadhguru undergoes emergency brain surgery, jokes 'doctors cut through my skull, but found nothing'

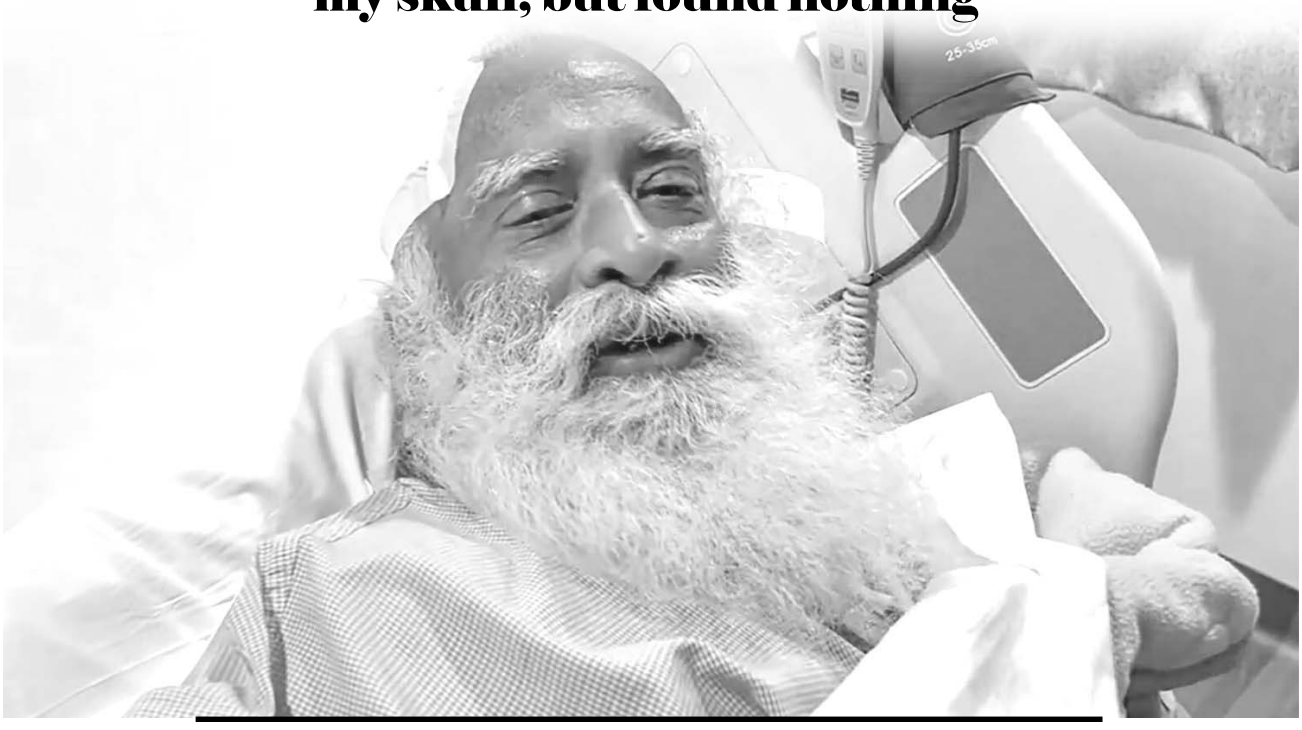

Sadhguru, the spiritual leader and founder of the Isha Foundation, underwent an emergency brain surgery due to bleeding in the skull. The condition was serious, as he had been experiencing severe headaches for four weeks before seeking medical attention. Despite his discomfort for the last four weeks, Sadhguru continued with his scheduled activities, including conducting the Maha Shivaratri event, Isha Foundation said. The severity of Sadhguru's condition became apparent after an urgent MRI was conducted on March 14 at Indraprastha Apollo Hospitals in Delhi, revealing a massive bleed in the brain, with evidence of both chronic and fresh bleeds, they said. Despite severe and agonizing symptoms, he completed his scheduled meetings on March 14, and the India Today Conclave on March 16 under the effect of a high dose of painkillers.

Initially hesitant to seek immediate medical attention due to his commitment to never missing a single meeting in the last 40 years, Sadhguru eventually agreed to hospitalization, Isha Foundation said. Sadhguru's neurological status deteriorated rapidly, with weakness in his left leg and worsening headaches with recurrent vomiting, they said. He was admitted to the hospital on March 17, where a CT scan revealed a significant increase in brain swelling and a life-threatening shift of the brain to one side. Despite these challenges, Sadhguru has been making steady progress in his recovery, with his brain, body, and vital parameters improving to normal levels. Neurologist Dr. Vinit Suri of Apollo Hospital said "We were joking with him that we have done what we could but you are healing yourself. The kind of improvement we are seeing is beyond our expectation. He is now extremely well. All his brain, body and vital parameters are normal and he is making a steady progress."

In a video posted on Sadhguru official 'X' account post-surgery, he lightened the mood by joking about the procedure, remarking, "The Apollo hospital neurosurgeons cut through my skull and tried to find something. But they found nothing... totally empty. They gave up and patched it up. Here I am in Delhi, with a patched-up skull but no damage." Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah took to 'X' to extend their heartfelt wishes for the speedy recovery of spiritual leader.

सीता सोरेन बीजेपी को क्या जिता पाएंगी दुमका लोकसभा सीट?

● **रवि प्रकाश**

वह साल 2009 के दिसंबर महीने की कोई तारीख थी। सीता सोरेन झारखंड की जामा विधानसभा क्षेत्र के हेमंतपुर गांव में सैकड़ों लोगों से रुबरू थीं। चारों तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के हरे झंडे लगे थे। सीता सोरेन मंच पर आई और आंखें बंद कर हाथ जोड़ लिए। उन्होंने शिबू सोरेन जिंदाबाद के नारे लगाए और कहा, उनके पति दुर्गा सोरेन ने उन्हें यहां साथ लेकर आने का वादा किया था। लेकिन, ऐसा नहीं हो सका। मैं अकेली आई हूं और मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। लोगों की भीड़ यह सुन 'झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद', 'शिबू सोरेन जिंदाबाद' और 'दुर्गा सोरेन अमर रहें' जैसे नारे लगाने लगी। पारंपरिक वाद्य यंत्र बजने लगे, तब सीता सोरेन ने अपना भाषण आगे बढ़ाया। उनकी उम्र तब सिर्फ 35 साल थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन के बड़े बेटे और उनके पति दुर्गा सोरेन की कुछ ही महीने पहले महज 39 साल की उम्र में ब्रेन हैमरेज से मौत हुई थी। वे जामा के विधायक रहे थे। लिहाजा, सीता सोरेन अपने पति की पारंपरिक सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ रही थीं। उन्होंने इसके लिए शिबू सोरेन को मनाकर पार्टी का टिकट लिया था। सियासत में उनकी एंट्री कुछ इस तरीके से हुई।

☞ **बढ़ती गई महत्वाकांक्षा :-** पति की मौत के बाद इत्तिफाकन राजनीति में आई सीता सोरेन ने अबतक लंबा सफर तय कर लिया है। उन्होंने जामा से कभी चुनाव नहीं हारा। वे तीन बार विधायक रहीं। इस दौरान उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ती रही। इस कारण उन्होंने शिबू सोरेन परिवार को कई दफा मुश्किलों में भी डाला। वे बार-बार कहती रहीं कि उनके पति दुर्गा सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन के वास्तविक उत्तराधिकारी थे। लिहाजा, अब यह हक उनका है। स्पष्ट था कि वे परोक्ष रूप से मुख्यमंत्री पद पर अपना हक जताने लगी थीं। इस पर परिवार में सहमति नहीं थी। पिछली जनवरी में उनके देवर और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के वक्त भी उनकी राय परिवार के दूसरे लोगों से अलग रही। इस कारण उनकी देवरानी कल्पना सोरेन का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चर्चाओं में आने के बावजूद चंपाई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बना दिए गए। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से ठीक पहले एक पत्र जारी कर चंपाई सोरेन को विधायक दल का नेता नियुक्त कर दिया था। उसी पत्र में उन्होंने सहयोगी पार्टियों के विधायकों से भी चंपाई सोरेन को समर्थन देने की अपील की थी। इसके बाद सीता सोरेन ने नई सरकार में मंत्री पद पर दावा किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि उन्हें बाबा यानि शिबू सोरेन का आशीर्वाद मिल चुका है। लेकिन, उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया और उनके सबसे छोटे देवर बसंत सोरेन चंपाई मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री बना दिए गए।

☞ **कैश फॉर वोट के आरोप :-** उनपर अपने पिता बोदु नारायण मांझी के जरिये साल 2012 के राज्यसभा

चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी से रिश्वत लेने के आरोप लगे थे। वे इससे संबंधित एक मुकदमे की नामजद अभियुक्त रही हैं। इस मामले में उनके रांची स्थित सरकारी आवास की कुर्की जब्ती की गई थी। इसके बाद उन्हें और उनके पिता को जेल में भी रहना पड़ा। इस मामले की जांच सीबीआई को दी गई थी। तब सीता सोरेन ने कुछ दिन फरार रहने के बाद कोर्ट में सरेंडर किया और उनके पिता को लंबी फरारी के बाद साल 2015 में भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया गया था। सीता सोरेन अपने खिलाफ आपराधिक मामला चलाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थीं। सालों से लंबित इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात जजों की संविधान पीठ ने पिछले 4 मार्च को साल 1988 के अपने फैसले को पलट दिया। इस खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि सांसदों और विधायकों को रिश्वत के मामले में विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। उनके खिलाफ भी आपराधिक मामले चलाए जा सकते हैं। नतीजतन, अब वे फिर से जांच के दायरे में आ गई हैं। उन्होंने अपने वयोवृद्ध ससुर शिबू सोरेन को भी मुश्किल में डाल दिया है क्योंकि, तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हाराव की सरकार को रिश्वत लेकर बचाने के आरोप वाला मामला शिबू सोरेन के खिलाफ अब दोबारा चलाया जा सकता है।

☞ **सीबीआई का खौफ और बीजेपी का दामन थामना :-** उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के एक मामले में भी लोकपाल ने सीबीआई को रिपोर्ट दर्ज कर जांच करने की इजाजत दे दी है। इस मामले में शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन भी आरोपी हैं। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने लोकपाल से यह शिकायत की थी। तब उन्होंने दावा किया था कि वे सोरेन परिवार के किसी सदस्य (दुर्गा सोरेन की बेटियों को छोड़कर) को चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रहने देंगे। इसके बाद सीता सोरेन ने बीते 19 मार्च को झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) की प्राथमिक सदस्यता और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने शिबू सोरेन को पत्र लिखकर अपने इस्तीफे की सूचना दी और आरोप लगाया कि उन्हें परिवार और पार्टी में पिछले 15 साल से उपेक्षा झेलनी पड़ी है। अब वे इस परिवार से अलग हो रही हैं। इस पत्र के सार्वजनिक होने के कुछ ही घंटे बाद वे दिल्ली में बीजेपी में शामिल हो गईं। तब बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस कांफ्रेंस भी हुई, जिसमें भी उन्होंने जेएमएम और सोरेन परिवार को लेकर कई बातें कहीं। उनके बीजेपी में शामिल होने से पहले ही पार्टी ने दुमका से अपने वर्तमान सांसद सुनील सोरेन को लोकसभा चुनाव का टिकट देने की घोषणा कर रखी थी। तब मीडिया में चर्चा चली कि बीजेपी उन्हें या उनकी बेटी को संथाल परगना की किसी सीट (दुमका नहीं) से चुनाव लड़ा सकती है। इसके छह दिन बाद 24 मार्च को बीजेपी ने दुमका सीट से अपना उम्मीदवार बदल कर सीता सोरेन को वहां से प्रत्याशी घोषित

कर दिया। यह शिबू सोरेन की पारंपरिक सीट रही है। वे यहां से कई बार सांसद रहे हैं। हालांकि बीजेपी के सुनील सोरेन ने उन्हें साल 2019 के लोकसभा चुनाव में शिकस्त दे दी थी। इसके बाद शिबू सोरेन जेएमएम प्रत्याशी के रूप में राज्यसभा के लिए चुन लिए गए। इन दिनों वे राज्यसभा सांसद हैं। यह भी इत्तिफाक है कि साल 2004 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सुनील सोरेन ने सीता सोरेन के पति दुर्गा सोरेन को चुनावी शिकस्त दी थी। अब सीता सोरेन ने दुमका लोकसभा सीट पर उनके हाथ से बीजेपी का मिला टिकट छीन लिया है।

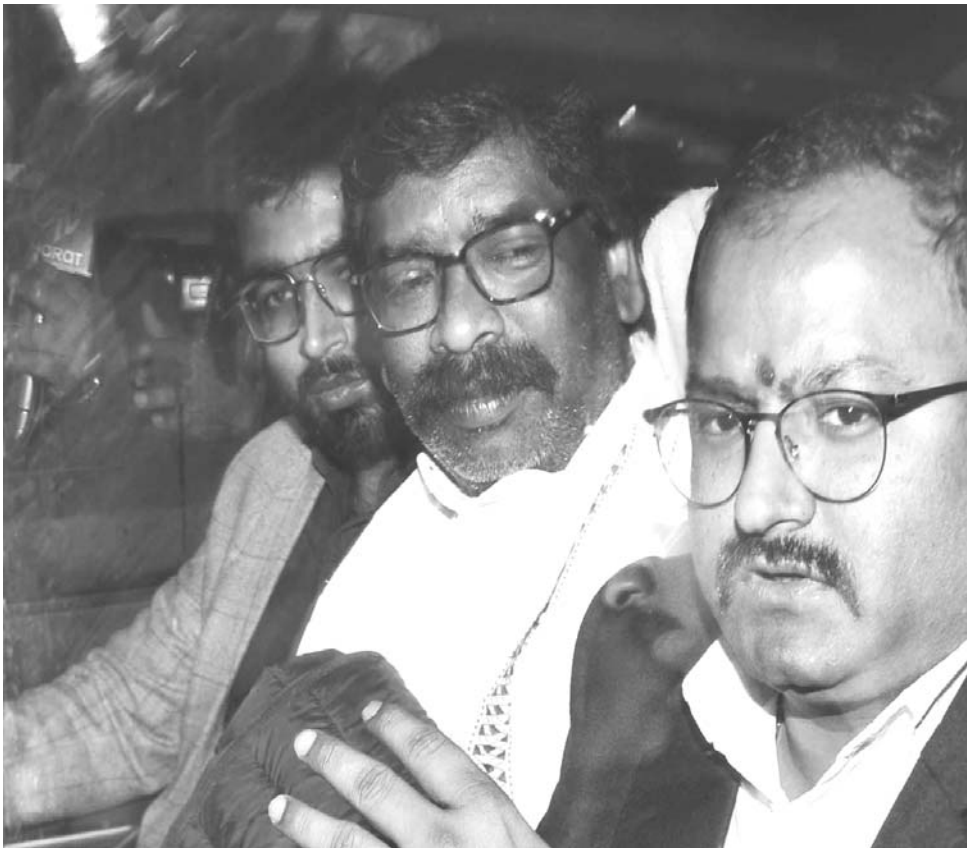

☞ **कितनी मुश्किल है दुमका की लड़ाई :-** दुमका में दशकों पत्रकारिता कर चुके वरिष्ठ पत्रकार आरके नीरद का मानना है कि सीता सोरेन के लिए दुमका की लड़ाई काफी मुश्किल है। आरके नीरद ने बीबीसी से कहा, "सीता सोरेन का राजनीतिक वजूद शिबू सोरेन की बहू होने की वजह से है। इसके बावजूद जामा सीट से पिछला विधानसभा चुनाव उन्होंने मामूली अंतर से जीता था। दुमका के लोग शिबू सोरेन के वोटर हैं, न कि सीता सोरेन के। उनके लिए जेएमएम से भी बड़ा नाम शिबू सोरेन का है। लिहाजा, सीता सोरेन को कोई चमत्कार ही यहां से जीत दिला पाएगा। वे लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगी।" "जेएमएम के वोटर उनके खिलाफ वोट करेंगे। बीजेपी के वोटरों का एक वर्ग सुनील सोरेन का टिकट कटने से नाराज है और वो बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा। बीजेपी को बस इतने भर से संतोष करना पड़ेगा कि उसने शिबू सोरेन के परिवार में फूट डाली है। यह सीट निकाल पाना पार्टी के लिए मुश्किल होगा।"

☞ **सीता सोरेन के मुकाबले कौन :-** स्थानीय मीडिया में चर्चा है कि शिबू सोरेन अपनी बढ़ती उम्र और बीमारियों की वजह से इसबार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते। ऐसे में इस सीट से उनके परिवार का कोई दूसरा सदस्य जेएमएम का उम्मीदवार हो सकता है। चर्चा है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि जेएमएम ने आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई घोषणा नहीं की है। समझा जाता है कि पार्टी अगले 1-2 दिन में अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। अगर हेमंत सोरेन यहां से जेएमएम प्रत्याशी बनते हैं, तो यह पहला मौका होगा जब शिबू सोरेन परिवार के दो सदस्य किसी चुनाव में आमने-सामने हों। वैसी स्थिति में दुमका की लड़ाई दिलचस्प बन जाएगी और सीता सोरेन की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उनके पक्ष में बड़ी सहानुभूति देखने को मिल रही है। उनका अपना जनाधार है और जेएमएम कार्यकर्ता उन्हें शिबू सोरेन का उत्तराधिकारी मानते हैं। वे अभी जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। हालांकि, हेमंत सोरेन की छवि परिवार को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति की रही है। उन्होंने या उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने सीता सोरेन या उनकी बेटियों के खिलाफ कभी कोई टिप्पणी नहीं की है। पारिवारिक समारोहों में वे साथ देखे जाते रहे हैं। सीता सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बाद जब कल्पना सोरेन ने सोशल मीडिया पर दुर्गा सोरेन को लेकर पारिवारिक बातें लिखकर उन्हें अपने पति का अभिभावक और पिता तुल्य बताया, तो सीता सोरेन और उनकी एक पुत्री ने अपने एक्स पोस्ट में उनके खिलाफ कड़ी टिप्पणी की। इसके बावजूद कल्पना सोरेन या परिवार के किसी सदस्य ने उसका प्रतिवाद नहीं किया। ऐसे में बहुत संभव है कि हेमंत सोरेन उनके मुकाबले चुनावी मैदान में नहीं उतरें। शिबू सोरेन चुनाव लड़ेंगे, इसकी संभावना भी नहीं है। वैसी स्थिति में यहां से जेएमएम किसी दूसरे नेता को अपना प्रत्याशी बना देगा।

☞ **सीता सोरेन का मायका :-** सीता सोरेन ओडिशा के मयूरभंज जिले के भगाबंदी गांव की रहने वाली हैं। उनके पिता बोदु नारायण मांझी इंडियन ऑयल में पदाधिकारी रहे हैं। उनकी मां मालती मुर्मू गृहिणी थीं। सीता सोरेन ने बारहवीं तक की पढ़ाई की है। उनकी और दुर्गा सोरेन की 3 बेटियां हैं। उनलोगों ने हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री रहते हुए एक गैर राजनीतिक संगठन दुर्गा सोरेन सेना का गठन किया था।

ISRO successfully lands Reusable Launch Vehicle named after legendary spaceship 'Pushpak'

The Indian Space Research Organisation (ISRO) marked a significant achievement with the successful execution of a landing mission for its Reusable Launch Vehicle (RLV) named "Pushpak" from the Aeronautical Test Range (ATR) in Karnataka's Chalakere on Friday. Taking off at approximately 7 a.m. from the Chalakere Runway, this mission represented the RLV's third landing endeavor, following previous successful missions in 2016 and April last year.

In a departure from conventional methods, the launch vehicle was lifted to an altitude of about 4.5 km by an Indian Air Force helicopter before being released upon meeting predetermined pillbox parameters. Emphasising the mission's significance, ISRO highlighted its integral role in ongoing efforts to develop essential technologies for a fully reusable launch vehicle, aimed at enabling cost-effective access to space. The winged vehicle, Pushpak (RLV-TD), executed an autonomous landing with precision on the runway after being released from an off-nominal position. ISRO Chairperson S Somanath underscored the importance of the Pushpak launch vehicle, characterizing it as India's bold step towards enhancing the affordability of space access. Somanath elaborated on the reusability of the upper stage, housing expensive electronics, which could potentially facilitate tasks such as refueling in-orbit satellites or refurbishing satellites, thereby contributing to space debris reduction.

The Reusable Launch Vehicle – Technology Demonstrator (RLV-TD) project stands as one of ISRO's most technologically challenging endeavors. Its primary objective is to develop crucial technologies for a fully reusable launch vehicle, ultimately aimed at reducing the cost of space missions. With a configuration resembling that of an aircraft but incorporating complexities from both a launch vehicle and an airplane, the RLV-TD serves as a flying test bed to evaluate various technologies, including hypersonic flight, autonomous landing, and powered cruise flight. ISRO envisions scaling up the RLV-TD to serve as the first stage of India's reusable two-stage orbital launch vehicle. In February, Somanath briefed Prime Minister Narendra Modi on the RLV mission during Modi's visit to the Vikram Sarabhai Space Centre in Trivandrum. The project, named after the legendary spaceship in the Ramayana, is estimated to have incurred a cost exceeding Rs 100 crore.

बिहार में बीजेपी ने पशुपति पारस को किनारे कर चिराग पासवान को क्यों चुना?

● चंदन कुमार जजवाड़े

बिहार में बीजेपी की अगुआई वाला गठबंधन एनडीए (नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस) ने लोकसभा चुनाव के लिए सीटों की साझेदारी की घोषणा कर दी है। राज्य की 40 लोकसभा सीटों में 17 पर बीजेपी, 16 पर जेडीयू, 5 पर चिराग पासवान की एलजेपी (आर) चुनाव लड़ेगी। एक-एक सीट जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से आई है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर अब भी स्थिति स्पष्ट नहीं है क्योंकि सोमवार को सीटों की साझेदारी की घोषणा हुई तो उपेंद्र कुशवाहा संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। इस साझेदारी में रामविलास पासवान के भाई और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के हिस्से में कुछ नहीं आया है। साल 2019 के मुकाबले दो नए साझेदारों को एनडीए में जगह देने के लिए नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने अपनी दो जीती हुई सीट छोड़ दी है। इसमें एक काराकाट लोकसभा सीट है जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से में आई है। वहीं जेडीयू ने पिछले चुनाव में जीती अपनी गया लोकसभा सीट भी जीतन राम मांझी की पार्टी हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के लिए छोड़ दी है। इन दो सीटों के बदले बीजेपी ने साझेदारी में जेडीयू को अपनी शिवहर लोकसभा सीट दे दी है। वहीं एलजेपी ने अपनी नवादा सीट बीजेपी के लिए छोड़ दी है। एलजेपी (आर) के हिस्से में वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई की सीट आई है। साल 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी और जेडीयू ने 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ा था जबकि एलजेपी के हिस्से में 6 सीटें आई थीं। इनमें केवल किशनगंज लोकसभा सीट पर जेडीयू की हार हुई थी और बाकघे सभी सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी।

☞ **चिराग पासवान की जीत :-** सीटों की इस साझेदारी में जिस पार्टी का हाथ खाली रहा है, वह चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस के धड़े वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। खास बात यह है कि साल 2021 में एलजेपी में टूट होने के बाद पशुपति कुमार पारस का धड़ा बीजेपी के साथ था और वो मंत्री पद पर भी थे। चिराग पासवान अकेले रह गए थे। लेकिन पार्टी में टूट के बाद भी चिराग पासवान बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे और लगातार सभाएं और रैलियाँ करते रहे। वहीं पशुपति कुमार पारस को जमीनी स्तर पर बहुत सक्रिय नहीं देखा गया। बीजेपी जब पशुपति पारस को तवज्जो दे रही थी तब भी चिराग खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते रहे और कहते थे कि पीएम उनके दिल में बसते हैं। चिराग ने पूरे सब्र के साथ इंतजार किया और बीजेपी को समझाने में कामयाब रहे उन पर भरोसा करना ज्यादा फायदेमंद है। साल 2020 में रामविलास पासवान के निधन के बाद साल 2021 में उनकी पार्टी एलजेपी दो हिस्सों में टूट गई थी। इस टूट में पार्टी के पाँच सांसद पशुपति कुमार पारस के साथ आ गए थे। उस वक्त बीजेपी ने भी पारस के धड़े को मान्यता दी थी। वरिष्ठ पत्रकार नचिकेता नारायण कहते हैं, "एलजेपी में टूट के बाद

चिराग पासवान अकेले रह गए थे और देखा गया कि एलजेपी समर्थकों की सहानुभूति चिराग पासवान के साथ थी। इसलिए मोदी उनको मनाने की कोशिश में काफी पहले से लगे हुए थे, नहीं तो बीजेपी के सामने भी पासवान वोटों के दूर जाने का खतरा था।"

☞ **चिराग की चतुराई :-** पार्टी में टूट के बाद माना जाता था कि चिराग पासवान के मन में बीजेपी को लेकर नाराजगी है। हालाँकि बाद में चिराग ने बीजेपी को लेकर संतुलित रवैया अपनाया। बीजेपी से दूर रहकर भी चिराग पासवान ने राजनीतिक चतुराई का बखूबी इस्तेमाल किया। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों के बाद से ही वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बयान देते रहे। यहा सिलसिला कुछ ही दिन पहले वैशाली में हुई चिराग पासवान की रैली तक मौजूद रहा लेकिन उन्होंने बीजेपी के खघ्लिाफ कभी मोर्चा नहीं खोला। इस दौरान चिराग पासवान ने राष्ट्रीय जनता दल से भी अपने संबंध मधुर बनाए रखे। वो तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी में भी दिखे और लालू परिवार के साथ पारिवारिक रिश्ते की बात करते रहे। हालाँकि चाचा पशुपति पारस से तल्खी और उनके केंद्र सरकार में मंत्री बने रहने के बाद भी चिराग ने बीजेपी से अपना नाता पूरी तरह नहीं तोड़ा और कभी आरजेडी के खेमे में नहीं गए। बिहार में पासवान बिरादरी के करीब 5।3% वोट हैं। पिछले कई चुनावों के आधार पर माना जाता है कि एलजेपी के पास बिहार में करीब छह फीसदी वोट हैं और इसमें बड़ा हिस्सा पासवान वोटरों का है। एलजेपी में टूट के बाद पशुपति पारस के गुट ने भले ही कोई चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन कई मौका पर चिराग पासवान ने साबित किया है कि एलजेपी के परंपरागत वोट उनके पास हैं।

☞ **एलजेपी के वोट चिराग के साथ? :-** चिराग पासवान ने साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी को बिना किसी गठबंधन के चुनाव मैदान में उतारा था। उन चुनावों में पार्टी को केवल एक सीट पर जीत मिली थी लेकिन करीब सात फीसदी वोट मिले थे। पार्टी में टूट के बाद से चिराग पासवान के गुट ने साल 2021 के अंत में बिहार में दो सीटों पर विधानसभा उपचुनाव लड़े थे। इन दोनों सीटों पर पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को बतौर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतारा था और उन्हें करीब 6 फीसदी वोट मिले थे। चिराग के साथ वोटों की इस ताकघ्त को देखते हुए बीजेपी ने भी कुढ़नी समेत बिहार के कई विधानसभा उपचुनावों में चिराग पासवान से अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार कराया था। वरिष्ठ पत्रकार सुरूर अहमद कहते हैं, "पशुपति पारस को आगे बढ़ाकर बीजेपी को कुछ नहीं मिलने वाला था। जो बीजेपी हर्षवर्धन और गौतम गंभीर जैसे अपने नेताओं को किनारे करने में समय नहीं लगाती उसे पारस को किनारे लगाने में कितना समय लगेगा।"

☞ **एनडीए को कितना खतरा :-** सुरूर अहमद का मानना है कि चिराग पासवान का राजनीति में भविष्य बचा हुआ है जबकि पशुपति पारस की उम्र की वजह से अब भविष्य उनके साथ नहीं है। एलजेपी (आर) के मुताबिकघ चिराग पासवान इस बार के लोकसभा चुनावों में हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे।

हाजीपुर लोकसभा सीट को रामविलास पासवान की सीट के तौर पर देखा जाता है। साल 2019 के चुनावों में पशुपति कुमार पारस यहाँ से चुनाव जीते थे। जबकि चिराग पासवान पिछले चुनावों में बिहार की ही जमुई लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर सांसद बने थे। नचिकेता नारायण कहते हैं, "पिछले दिनों चिराग पासवान ने जमुई में कहा था कि वो कभी

जमुई को नहीं छोड़ेंगे। अब देखना होगा कि वो जमुई सीट को लेकर क्या फैसला करते हैं। यही नहीं अब पशुपति पारस की नजर होगी कि वो क्या करेंगे।" पशुपति कुमार पारस लगातार यह दावा करते रहे हैं कि रामविलास पासवान के असली राजनीतिक उत्तराधिकारी वही हैं और रामविलास ने खुद जीवित रहते हुए उन्हें हाजीपुर सीट से चुनाव लड़वाया था। अब लोकसभा चुनावों के लिहाज से एनडीए में पारस के पास कुछ नहीं बचा है तो ऐसे में उनके अगले कदम पर सबकी नजर होगी।

☞ **पशुपति पारस का अब क्या होगा? :-** नचिकेता नारायण कहते हैं, "राजनीति में पशुपति पारस की पारी अब खत्म हो गई दिखती है। लेकिन उनके साथ इस व्यवहार को विपक्षी गठबंधन जनता के सामने कितना भूना पाता है, यह देखना दिलचस्प होगा।" जेडीयू इस तरह का आरोप लगा चुकी है कि साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में चिराग पासवान ने जेडीयू के उम्मीदवारों को हराने के लिए एनडीए में रहकर भी अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। ऐसे में नीतीश और चिराग पासवान के एक साथ होने से क्या एनडीए के सामने कोई खतरा भी हो सकता है? सुरूर अहमद कहते हैं, "नीतीश की पार्टी के कमजोर होने के पीछे जिस तरह से चिराग पासवान को जिम्मेवार बाताया जाता है, अगर यह सच है और लोकसभा चुनावों में दोनों दलों का वोट एक-दूसरे को ट्रांसफर नहीं हुआ तो इसका नुकसान एनडीए को हो सकता है।" बिहार में फिलहाल एनडीए में सीटों की साझेदारी को लेकर फैसला हुआ है और माना जाता है कि अब जल्द ही विपक्षी खेमें में भी सीटों की साझेदारी हो जाएगी। बिहार के सियासी गलियारों में यह भी चर्चा है कि मुकेश सहनी के दल वीआईपी के साथ बात तय हो जाती है तो बीजेपी अपने कोटे की एक सीट वीआईपी को दे सकती है। हालाँकि इस सियासी उठापकट में अभी बहुत से पन्ने खुलने की संभावना है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के साथ ही ये पन्ने भी खुलने लगेंगे। लोकसभा चुनावों में एनडीए में सीटों की साझेदारी की घोषणा होते ही सभी संभावनाओं और अटकलों पर विराम लग गया है।

Why ancient Jewish commandments are still relevant?

There's a lot said about Jews, there's a lot written about Jews, but no one really knows anything about Jews," says Mirna Funk. Speaking to DW, the 43-year-old Berlin journalist and writer said she did not grow up with Jewish traditions. But she's since learned a lot about Jewish history and culture, and she's summarized the most important lessons she's gleaned in her new book, "Von Juden lernen" (Learning from Jews).

The mission: to improve the world

Mirna Funk is in the shower and struggling with life: There's the war in Ukraine, not enough money in her bank account, no lover in sight — couldn't God intervene? But complaining contradicts the Jewish commandment of "Tikkun Olam," which means repairing the world. While the Christian tradition calls on believers to wait patiently for the Last Judgement and the return of the Messiah who will then bring them paradise, Judaism calls for personal initiative: "God expects activity, not passive torpor and the illusory belief that things will somehow work out," Funk explains. So the mission is to get down to the work of improving the world. But a paradise on Earth is a utopian dream, says Funk. "Humans always have both positive and negative qualities, so they can't make this world into a paradise." But, she says, we can at least try to do our best.

Helping people to help themselves

Part of improving the world involves helping those in need. "It's not a virtue, but an obligation," Funk writes. The concept is called "Tzedakah" in Hebrew, which translates to both "righteousness" and "charity." Giving alms is the lowest level of tzedakah. The real aim is to give work to those in need so that they are not dependent on others. Because of that, Funk is critical of those in Germany calling for a universal basic income. She advocates personal responsibility: "It is important not to leave people dependent and without freedom by restricting their independence through financial assistance."

A disobedient Eve

Christianity teaches that Eve is to blame for man's banishment from Eden. Against God's will, she ate an apple from the Tree of Knowledge and tempted Adam to do the same. But to Mirna Funk, Eve is a rebel. Tolerating dissent is a cornerstone of the Jewish tradition, which relies on dialogue and does not demonize those who disagree. That also applies to partnerships. You shouldn't try to become as similar as possible, because, as Funk says, "There is no movement without friction, no growth without criticism." And because women are not simply yea-sayers, they do not take on the role of the obedient companion in Judaism. More than 3,000 years ago, King Solomon wrote the poem "Eshet Chayil," which translates as "woman of valor" and is still sung on Shabbat today. "In this song of praise, the woman looks after the children, bakes and cooks, but at the same time she has her own business," says Funk. "She is strong, she is brave, she is courageous."

This image of women characterizes the Jewish community. "Israel had a female prime minister in the 1970s, Golda Meir," says Funk. "While women in West Germany weren't even allowed to open their own bank accounts, Israel already had a female politician running the country."

How can that self-assurance be reconciled with the image of the modestly dressed Jewish woman in a wig who owes her husband obedience and, above all, is supposed have as many children as possible? Mirna Funk says those are the Orthodox and Ultra-Orthodox, and they make up the smallest part of the world's Jewish population. "That is simply

a cult-like sect, and they exist in every religion. A lot is written about them, but for me they are not relevant because they don't play a major role in Judaism."

A right to good sex

Women also have the right to good sex, according to the Torah. As the Jewish scholar Maimonides (1138-1204) wrote: "A man has the duty to satisfy his wife in sexual matters." If he did not, she had the right to divorce him. Women's sexuality was therefore never taboo in Judaism, and chastity was not elevated to an ideal as it was in Christianity. "Yada" is the name of sexual union — "to recognize each other and to enter into a relationship with God through the act."

Feathers in the wind and social media pile-ons

In a well-known Jewish story, a man spreads lies about another person, then feels guilty about it and consults his rabbi. "What should I do?" he asks. The rabbi advises him to slit open a pillow and throw all the feathers to the wind. The man follows the instructions and goes back to the rabbi. "And now collect all the feathers again," he tells him. "Impossible!" shouts the man. "You see," replies the rabbi, "it's like the rumors you spread about another person. You can never undo them." That's precisely why defamation ("lashon hara") is considered a grave sin in Judaism, even worse than murder.

The modern variant of this all-too-human foible is the social media pile-on. According to Funk, that's no longer an unusual phenomenon, but rather the rule. "It shows in a frightening way that the opinion of others is disregarded as soon as it does not agree with our own. The person exposed to the pile-on is defamed and degraded." She says that dialogue doesn't have a chance under this polarized viewpoint, because "what constitutes the pile-on is the totalitarian denial of otherness." Judaism rejects this view and does not divide the world ideologically into good and evil. Instead of condemning others, one should learn to argue properly: "Machloket" is considered a method of exploring different points of view and is seen as a sign of dedication and respect. Funk says that this nuanced perspective has been lost in the current social climate.

In dialogue with the past

Jewish American writer Elie Wiesel once said, "To be Jewish is, above all, to safeguard memory." According to Funk, that has changed. She says we now live in a time that has forgotten history, in which the focus is on the present. "When terms such as apartheid, genocide, ethnic cleansing and colonial power have increasingly been applied to Israel since October 7, 2023 and sold as truth, that reveals an absolutely inadequate understanding of history." She observes a very young generation becoming politicized and positioning itself against Israel. "Terms that are so historically loaded, like apartheid, immediately trigger emotions in others." What she finds especially frightening is that, "Now even German or European Jews are being attacked because of this war." She says it's that much more important to never forget the past, but to enter into a dialogue with it and create a deliberate future out of it.

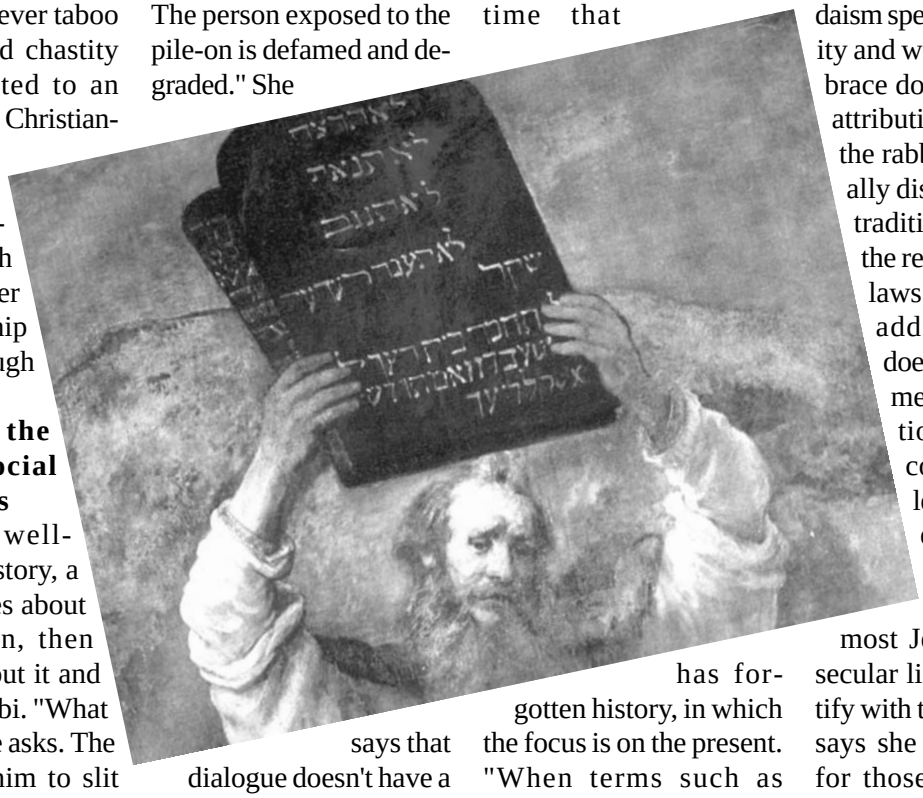

As current as ever

"What makes Judaism special is its flexibility and willingness to embrace doubt," says Funk, attributing that aspect to the rabbis who continually discarded outdated traditions and adapted the religion's rules and laws to the times. She adds that Judaism doesn't focus only on metaphysical questions, but always considers the dilemmas of human existence. "Those are all reasons why most Jews who lead a secular life can still identify with the religion." She says she wrote her book for those people — but also for anyone who immediately associates Jews with the Holocaust, antisemitism, or the Arab-Israeli conflict. "As if that were all that Jewish life or culture or Jewishness was about." Mirna Funk's book proves there is much more to it than that.

खेरौना : वो गांव जिसने अमेठी को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई

● **समीरात्मज मिश्र**

अमेठी जिले का खेरौना वो गांव है जिसकी वजह से अमेठी लोकसभा क्षेत्र एक सामान्य सीट से वीआईपी सीट बन गया। क्या है इस गांव के एकाएक चर्चित होने की कहानी? मई 1976 की बात है। देश में आपातकाल लगे करीब एक साल होने जा रहा था। आपातकाल के दौर के सबसे ताकतवर व्यक्ति कहे जाने वाले संजय गांधी राजनीतिक परिदृश्य में तो काफी चर्चित और ताकतवर हो चुके थे, लेकिन राजनीति में उनका औपचारिक प्रवेश तब तक नहीं हुआ था। उनके इसी राजनीतिक प्रवेश के लिए सुल्तानपुर जिले के अमेठी कस्बे को चुना गया। यहां के चुनाव की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। एक दिन संजय गांधी अमेठी पहुंचे, उनके साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायणदत्त तिवारी समेत कई बड़े कांग्रेसी नेता भी थे। ये सभी खेरौना नाम के एक गांव में आए और तय हुआ कि यहां कांग्रेस पार्टी के लोग श्रमदान करेंगे। यहीं से संजय गांधी की राजनीतिक जमीन तैयार की जानी थी। उनके इस फैसले से यह गुमनाम सा गांव अचानक देश और दुनिया के अखबारों की सुर्खी बन गया।

☞ **श्रमदान से सड़क बनाई :-** खेरौना गांव, अमेठी कस्बे से बिल्कुल लगा हुआ है। संजय गांधी अपने कुछ युवा साथियों के साथ जब यहां पहुंचे, तो फावड़ा चलाकर उन्होंने सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया। इसी से शुरू हुआ श्रमदान का वह सिलसिला, जो एक महीने से भी ज्यादा चला और इससे अमेठी कस्बे में तीन सड़कें तैयार की गईं। संजय गांधी के साथ देश भर से बड़ी संख्या में युवा कांग्रेसी यहां श्रमदान के लिए आकर जुटे थे। श्रमदान के लिए सैकड़ों फावड़े, कुदाल, टोकरे जैसी चीजें यहां पहले ही पहुंचाई जा चुकी थीं। स्थानीय पत्रकार योगेश श्रीवास्तव बताते हैं कि श्रमदान एक महीने से भी ज्यादा समय तक चला और इस दौरान बाहर से आए सभी लोग यहीं रुके थे। उनके ठहरने के लिए खेरौना गांव और अमेठी कस्बे में ही इंतजाम किया गया था। स्थानीय लोगों के घरों में ही सभी के रुकने की व्यवस्था की गई थी। योगेश श्रीवास्तव याद करते हैं, बाहर से आए लोगों के लिए खाना यहीं बन रहा था। रुकने की व्यवस्था गांव के लोगों ने अपने घरों में कर रखी थी और मेहमानों के मनोरंजन के लिए शाम को कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते थे। कुल मिलाकर डेढ़ महीने तक यहां उत्सव का माहौल बना हुआ था।

☞ **कई ने तो पहली बार पकड़ा था कुदाल :-** न सिर्फ देशभर से आए युवा कांग्रेस के तमाम नेता श्रमदान में तत्परता से लगे रहे, बल्कि पूरा सरकारी अमला भी खिदमत में मौजूद था। इस दौरान खेरौना के अलावा विराहिनपुर और मलिक मोहम्मद जायसी की मजार का कच्चा रास्ता बनाने के लिए युवा नेताओं ने खूब पसीना बहाया, फावड़े-कुदाल चलाए और आखिरकार डेढ़ महीने के भीतर तीनों सड़कें तैयार हो गईं। स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं कि इनमें कई लोग तो ऐसे थे जिन्होंने जिंदगी में पहली बार कुदाल-फावड़ा थामा था। कुछ ने तो शायद इन्हें पहले कभी देखा तक नहीं था। राम नरेश शुक्ल तब खेरौना गांव के प्रधान थे। उनके बेटे राजेंद्र प्रसाद शुक्ल उस समय को याद करते हुए बताते हैं, गजब का माहौल था। इसी श्रमदान से संजय गांधी की राजनीति शुरू हुई थी। जिन तीन सड़कों पर श्रमदान हुआ था, बाद में वो पक्की हो गईं। डेढ़ महीने तक तो यहां मेला लगा था। अलग-अलग राज्यों से लोग आ रहे थे, श्रमदान कर रहे थे और फिर चले जाते थे। उसके बाद दूसरे लोग आते थे। बड़े-बड़े अफसर यहां डेरा डाले हुए थे।श

☞ **गांधी परिवार की पारंपरिक सीटें :-** संसदीय क्षेत्र के रूप में अमेठी 1967 में अस्तित्व में आया था। पड़ोस की रायबरेली सीट से संजय गांधी के पिता फिरोज गांधी और उनके बाद इंदिरा गांधी चुनाव लड़ती थीं। 10 साल तक तो अमेठी एक सामान्य संसदीय सीट के रूप में ही रही, लेकिन संजय गांधी के श्रमदान के बाद यह एक वीआईपी सीट के रूप में तब्दील हो गई। यह रुतबा आज तक कायम है। हालांकि, श्रमदान के तत्काल बाद 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में संजय गांधी इस सीट से हार गए। लेकिन उसके बाद गांधी परिवार या उनके करीबियों ने जीत का जो सिलसिला बरकरार रखा, वो 2014 तक चला। 2019 में हुए पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया। हालांकि उसके पहले भी 1998 में यह सीट एक बार बीजेपी के खाते में गई थी। तब डॉक्टर संजय सिंह ने बीजेपी से

जीत दर्ज की थी। संजय सिंह एक बार फिर बीजेपी में हैं। खेरौना गांव में संजय गांधी ने जब श्रमदान किया था, तब मुख्य रूप से वो काम संजय सिंह की ही देखरेख में हुआ था। संजय सिंह की गांधी परिवार, खासतौर पर संजय गांधी से काफी नजदीकी थी।

☞ **श्रमदान के लिए खेरौना को ही क्यों चुना?** :- पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय सिंह अमेठी राजघराने से संबंध रखते हैं। कुछ समय पहले जब वो कांग्रेस पार्टी में थे, तब उन्होंने इस श्रमदान महोत्सव के बारे में विस्तार से बात की थी। उनका कहना था, मान के चलिए कि यूथ कांग्रेस के करीब 1,000 लोग यहां आए थे। कुछ तो चार-छह दिन रहकर चले जाते थे, लेकिन बहुत से लोग लगातार यहीं रहे। रात दिन मजमा लगा रहता था। संजय गांधी ने मुझसे कहा था कि आपको यहीं रहना है, खिसकना नहीं है। मैं खिलाड़ी था, लेकिन उनके कहने के बाद मैं भी खेल-वेल सब छोड़कर अपने दोस्तों के साथ डटा रहा। इस गांव को ही श्रमदान के लिए क्यों चुना गया, इसका किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। अमेठी के एक कांग्रेस नेता उमाकांत द्विवेदी बताते हैं कि साल 1971 के चुनाव में खेरौना गांव में एक जनसभा हुई थी। उस जनसभा में इंदिरा गांधी भी आई थीं और काफी भीड़ जमा हुई थी। उमाकांत द्विवेदी बताते हैं, जब अमेठी संसदीय क्षेत्र को संजय गांधी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत के रूप में चयनित किया गया, तो खुद संजय गांधी ने यहां से चुनाव लड़ने से पहले विकास कार्य करने की शुरुआत की। इसी क्रम में श्रमदान का फैसला लिया गया। एक बात यह भी थी कि खेरौना गांव अमेठी कस्बे से बिल्कुल लगा हुआ भी है। बाद में संजय गांधी के सांसद बनने के बाद से ही यह क्षेत्र वीआईपी क्षेत्र के रूप में जाना जाने लगा। गांव में और भी कई सड़कें बनीं, स्कूल बने। लेकिन उस दौर के लोग सबसे ज्यादा उस उत्सवधर्मी माहौल को ही याद करते हैं।

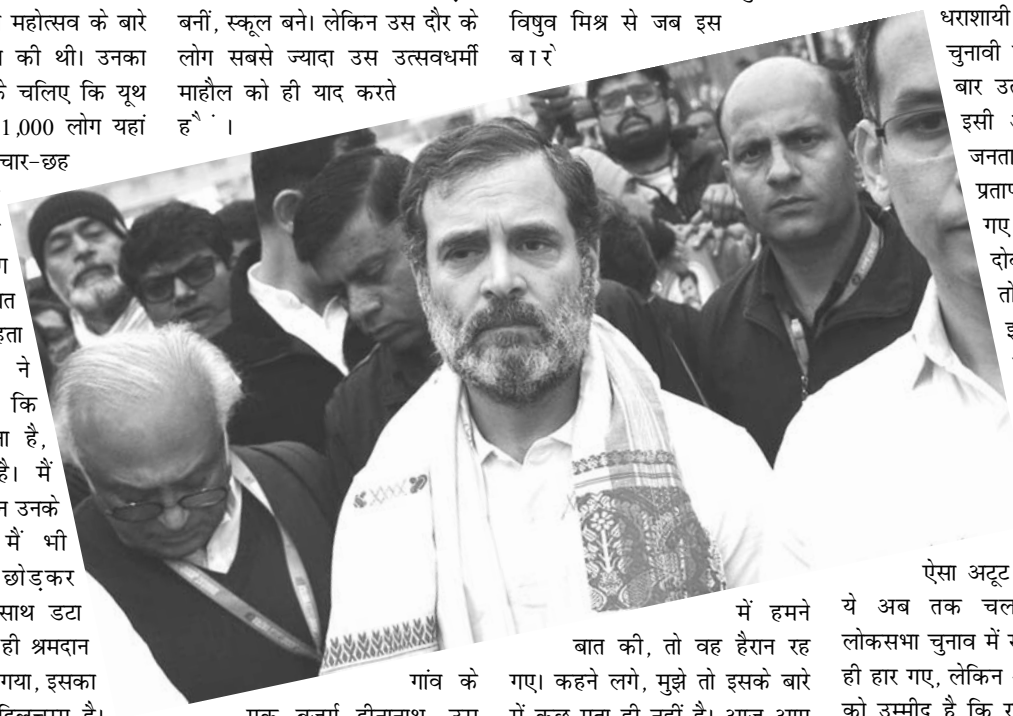

गांव के एक बुजुर्ग दीनानाथ, उस समय युवा थे। वह याद करते हैं, गांव के तमाम लोग तो इसलिए भी भीड़ लगाए रहते थे कि शहरों के बड़े-बड़े लोग यहां फावड़ा चला रहे थे। यह देखकर गांव वालों को आश्चर्य होता था। इसके अलावा इतनी सुंदर और स्मार्ट लड़कियां भी फावड़ा चला रही थीं, यह देखकर लोगों को भरोसा ही नहीं होता था।

☞ **बुजुर्ग महिलाएं क्या बताती हैं?** :- हालांकि खेरौना और दो अन्य गांवों में तीन सड़कें बनीं, कुछ और भी काम हुए, लेकिन किसी भी काम की कोई निशानी नहीं है यहां। यानी कोई पत्थर या निशान नहीं है। यहां तक कि गांव के तमाम युवकों को तो इसके बारे में बहुत ज्यादा मालूम भी नहीं है। अमेठी कस्बे के ही निवासी और बीजेपी के युवा नेता विषुव मिश्र से जब इस बारे में हमने बात की, तो वह हैरान रह गए। कहने लगे, मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। आज आप ही से पता लग रहा है, जबकि खेरौना गांव में तो मेरा लगभग रोज आना-जाना है। हालांकि, खेरौना गांव की कई बुजुर्ग महिलाओं को वो दौर भली-भांति याद है। एक महिला उर्मिला देवी कहती हैं कि उस जमाने में औरतें घरों से ज्यादा नहीं निकलती थीं, लेकिन इतनी भीड़ लगी रहती थी कि उसे देखने के लिए लड़कियां-महिलाएं भी दिन भर चक्कर लगाती रहती थीं। वह बताती हैं, दूसरी जगहों से आई महिलाएं और लड़कियां जब यहां काम कर रही थीं, तो देखा-देखी यहां की औरतें भी हाथ बंटाने लगतीं। खेरौना गांव में हुए इस श्रमदान के चलते जो उत्सवधर्मी माहौला बना था, वो अगले ही साल यानी 1977 के लोकसभा चुनाव में धराशायी हो गया क्योंकि चुनावी मैदान में पहली बार उतरे संजय गांधी इसी अमेठी सीट से जनता पार्टी के रवींद्र प्रताप सिंह से हार गए। 1980 में जब दोबारा चुनाव हुए, तो संजय गांधी ने इस सीट पर भारी बहुमत से चुनाव जीता। उसके बाद से अमेठी संसदीय सीट का गांधी परिवार से ऐसा अटूट रिश्ता बना कि ये अब तक चला। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी भले ही हार गए, लेकिन अमेठी के लोगों को उम्मीद है कि राहुल गांधी एक बार फिर यहां से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी का अमेठी सीट से अब तक किसी उम्मीदवार की घोषणा न करना भी उनकी उम्मीदों को मजबूत करता है, लेकिन संशय बरकरार है।

Patanjali misleading ads : SC orders Ramdev, Acharya Balkrishna to appear personally in court

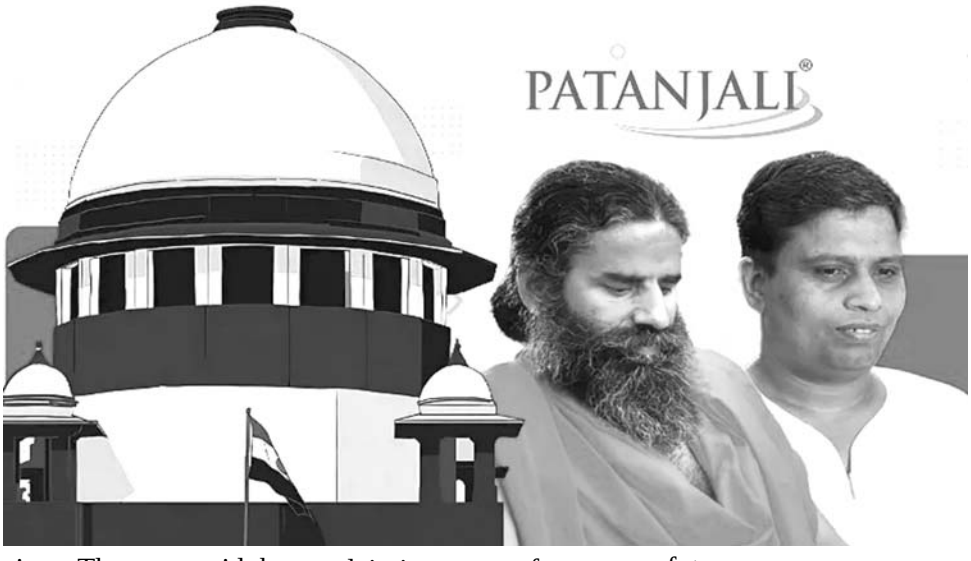

The Supreme Court has directed Patanjali Ayurved Ltd's co-founder Baba Ramdev and managing director Acharya Balkrishna to personally appear before it and explain why no reply was filed on a contempt notice issued against them over showing misleading advertisements on medicinal cures. A bench of Justice Hima Kohli and Justice Ahsanuddin Amanullah observed that neither Ramdev nor Balakrishna had filed any response to the show cause notice issued to them by the court on misleading claims made in advertising their medicines. The court said they should personally appear within two weeks to explain their stand.

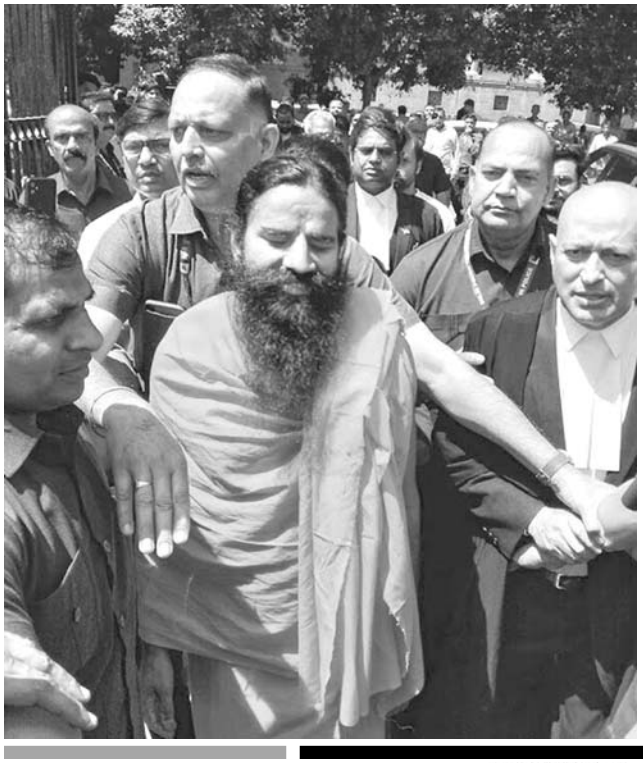

On February 27, the apex court imposed a ban on the advertisements being shown by Patanjali claiming a cure for some of the incurable diseases, which is not permitted under the rules as their authenticity was not proven. The bench further recorded that the medicines claimed to cure certain diseases as per Ramdev's company Patanjali's version without any empirical evidence. The court even noted that claims made by Baba Ramdev's company had taken the country for a ride as those were misleading. The matter relates to a plea filed by the Indian Medical Association (IMA) alleging that a smear campaign was carried out by Baba Ramdev and his company against the COVID-19 vaccination and modern medicine. In November last year, the court also directed Patanjali not to publish false advertisements in the future.

Patanjali had then undertaken not to publish advertisements making false claims about its products and targeting modern medicines and vaccinations, but it continued to do so, the court was told today. As senior Advocate Mukul Rohatgi appeared before the Court on behalf of Ram Dev and his company, the bench noted that the appearance of senior counsels on Ram Dev's behalf showed that they were in fact aware of the show cause being issued in their names. Noting that the Central government had also not tackled the issue of misleading advertisements, the court directed Baba Ramdev and others to personally appear before the court and reply to the show cause notice issued by the court.

मैं हूं ना : सीजेआई धनंजय यशवंत चंद्रचूड़

सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़ भले चुनाव नहीं लड़ रहे हों, लेकिन समाज में ऐसे कई लोग मिल जाएंगे, जो उन्हें उम्मीदों का अन्तिम खुला रोशनदान मान रहे हैं। संदर्भ है उनके द्वारा लगातार दिए गए, बेहद चर्चित फैसले। जैसे हाल का इलेक्टोरल बांड से संबंधित फैसला। भारतीय राजनीति में पहले भी देश की तकदीर पलटने वाले सुप्रीम या अन्य अदालतों ने दिए हैं, लेकिन चूंकि हम कमजोर याददाश्त के शिकार लोग हैं, इसलिए ताजा हवाले देना जरूरी हो जाता है। चुनाव न लड़ने के बावजूद चंद्रचूड़ के फैसलों ने इंसाफ के हुकूमत में लोगों की न सिर्फ आस बढ़ा दी, पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार हो या अन्य राजनीतिक दल, सभी के मन में अन्याय के प्रति डर पैदा कर दिया है। यदि उनके निर्णयों से 2024 के लोकसभा चुनावों में बाजी पलट भी जाए, तो हैरत नहीं होनी चाहिए। हाल में एक टीवी चौनल से की गई बातचीत में चंद्रचूड़ ने अपनी जातीय जिंदगी की किताब के कई यादगार तथा पठनीय पन्ने खोले।

☞ **पत्नी सबसे अच्छी दोस्त :-** उन्होंने कहा कि उनकी सबसे अच्छी दोस्त उनकी पत्नी कल्पना दास है। दोनों ही शुद्ध शाकाहारी हैं और मोटा अनाज नहीं आयुर्वेदिक भोजन करते हैं। उनका मत है कि भोजन का सीधा रिश्ता आपके दिल और दिमाग से होता है। चंद्रचूड़ ने बताया कि उनका भोजन पौधों से उत्पादित अनाज से बनता है। वे तड़के साढ़े तीन बजे उठ जाते हैं। वे कहते हैं इस वक्त चूंकि वातावरण शांत रहता है, इसलिए उन्हें कुछ देर योग करने में सुविधा होती है। साथ ही वे योग के बाद चौन और सुकून से विचार भी कर पाते हैं। उन्हें आइस्क्रीम भी पसंद है। एक अंग्रेजी पत्रिका से हुई चर्चा में उन्होंने बताया था कि वे पहले जितना पढ़ पाते थे, अब नई जिम्मेदारियों के तहत पढ़ नहीं पाते, मगर कुछ पन्ने पढ़ना उनकी आदत में आज भी शुमार है। चंद्रचूड़ की खास बात यह है कि उनकी जिंदगी का एकमात्र मिशन है कि आम आदमी मैं यह भरोसा पैठ जमाए कि न्याय पाना उनका हक है और इसी के लिए मैं आधी रात में भी कोई मेल आता है, तो तुरंत उस पर कार्यवाही की व्यवस्था करता हूं। बता दें कि पिछले दिनों चंद्रचूड़ अपने साथी जजों के साथ जिला स्तर की कोर्ट की समस्याओं को समझने के लिए गुजरात के कच्छ एक सम्मेलन में गए थे। वहां से लौटकर उन्होंने देश की जिला कोर्ट परिसरों में कुल 18000 ई-मेल सेंटर पायलट प्रोजेक्ट के तहत खुलवाए ताकि जिन लोगों के पास आधुनिक तकनीकी साधन उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें भी शीघ्र, सरल, सस्ता न्याय उपलब्ध हो।

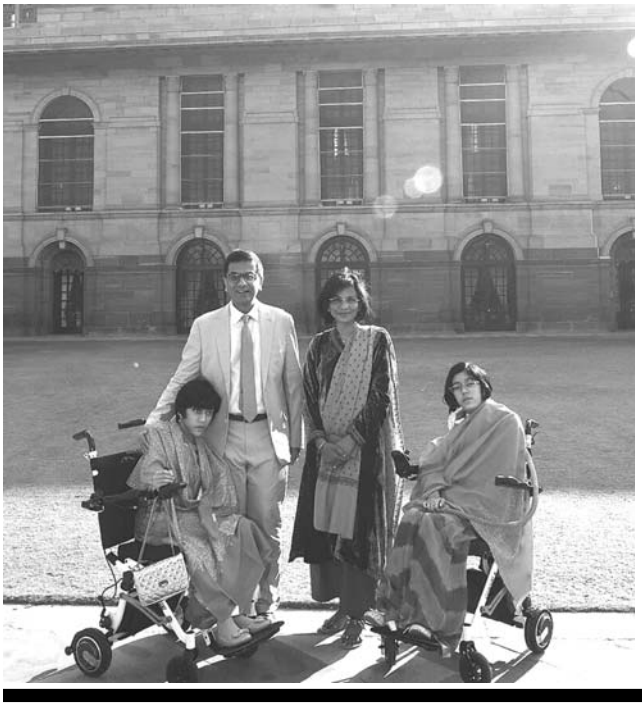

☞ **पिता वायवी चंद्रचूड़ भी सीजेआई रहे :-** चंद्रचूड़ के पिताजी वायवी चंद्रचूड़ भी देश के सर्वोच्च न्यायाधीश रहे और उनका कार्यकाल इस पद पर अब तक सबसे लंबा रहा। चंद्रचूड़ कविताई या पोएटिक अंदाज में फैसले लिखने के लिए भी मशहूर हैं। वे जब बांबे हाईकोर्ट के जज थे, तब उन्होंने हरे रंग की कार खरीदी थी, जो उनकी पहचान बन गई थी। उनका जन्म 1959 की 11 नवंबर को मुंबई में हुआ था। वे देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप इसी साल यानी 2024 के नवंबर में रिटायर होंगे। तब देश में 18वीं लोकसभा के आम चुनाव सम्पन्न हो चुके होंगे। उनकी कही यादगार बात कि देश के किसी भी नागरिक को तुरंत न्याय दिलाने के लिए दूरदराज से दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। आधुनिक तकनीक के माध्यम से वह अपने मूल स्थान से ही हम लोगों से सम्पर्क कर सकता है, को सुनकर शाहरुख खान द्वारा अभिनीत हिट फिल्म के टाइटल 'मैं हूं ना' की याद आती है।

Surrender of Pirates from Pirate Ship Ex MV RUEN

Firm actions by the Indian Navy resulted in surrender of the Pirate Ship ex-MV Ruen on 16 March 2024. In an operation lasting over 40 hours that commenced in the early hours of 15 March 2024, INS Kolkata intercepted Pirate Ship ex-MV Ruen in the Arabian Sea based on inputs received by IFC-IOR from UKMTO. As per the input, the ship was appreciated to be used as a Mother Ship for undertaking piracy attacks and hijacking of merchantmen. INS Kolkata commenced shadowing the Pirate Ship in early hours of 15 Mar 2024. Prior day break, the vessel upon sighting INS Kolkata reversed course and started heading towards the Somali Coast. Several armed pirates were observed on upper deck of the ship.

INS Kolkata directed the Pirate Ship to stop for investigation in accordance with International Law, especially the United Nations Conventions on the Laws of the Sea(UNCLOS). However, the Pirate Ship refused to comply and instead opened fire. INS Kolkata thereafter acted in self-defence and used kinetic measures required to disable the ship and compel the pirates to surrender. INS Subhadra joined INS Kolkata in the operation. Further, Indian Navy undertook long range deployment and para drop of Marine Commandos over sea in vicinity of the pirate ship using C17s in coordination with Indian Air Force. Aerial surveillance for the operation was undertaken by Indian Navy P8I aircraft, Sea Guardian UAV, and the ship's integral helicopters and spotter drones. In the face of decisive action by the Indian Navy, all pirates onboard surrendered. The 35 pirates and 17 crew members were duly taken into custody and shifted to Indian Naval ships. Thereafter, Indian Navy specialists searched and sanitised the ship with respect to arms, ammunition and contraband, rendering it safe. In addition, assessment of seaworthiness and essential repairs were undertaken by naval technical team, for making the ship fit for further voyage.

On request from the ship's original company, M/s Navibulgar, and the Master, the crew of MV Ruen were reinstated onboard the ship, which reverted her to earlier status and the ship hoisted the flag of Malta. MV Ruen thereupon proceeded under own power to the next port of Salalah (Oman), as decided by the company, under escort of INS Subhadra to safeguard it against further pirate attack. INS Kolkata, with the 35 apprehended pirates returned to Mumbai on 23 March 2024 and handed over the Pirates to the local police for further legal action in accordance with Indian laws, specifically the Maritime Anti Piracy Act 2022. Indian Navy displayed high degree of professionalism and upheld the principles of international law and commitment to ensuring safe seas and maritime security in the region. As part of the ongoing Operation Sankalp, Indian Navy ships are deployed in the Arabian Sea and Gulf of Aden towards safety of seafarers and mercantile trade passing through the region.

फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनी को जानिए

● राघवेंद्र राव और शादाब नजमी

चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा वो डेटा सार्वजानिक कर दिया जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उसे 12 मार्च को उपलब्ध करवाया था। इस डेटा के मुताबिक जिस कंपनी ने सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे उसका नाम फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। अक्टूबर 2020 और जनवरी 2024 के बीच इस कंपनी ने 1368 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। लेकिन इस कंपनी की चर्चा इसलिए भी हो रही रही क्योंकि अतीत में इस पर ईडी (एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट) या प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाइयां भी होती रही हैं। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने इलेक्टोरल बॉन्ड की सबसे बड़ी खेप अक्टूबर 2021 में खरीदी जब उसने 195 करोड़ रुपये के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। जनवरी 2022 में दो बार में इस कंपनी ने 210 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड खरीदे। इस कंपनी की सबसे हालिया खरीद इस साल जनवरी में की गई जब उसने 63 करोड़ रुपये के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे।

☞ **फ्यूचर गेमिंग के बारे में क्या है मालूम** :- फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को 30 दिसंबर 1991 में बनाया गया था। इस कंपनी का रजिस्टर्ड पता तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है, लेकिन इसका वो पता जहाँ खाते की किताबें रखी जाती हैं वो कोलकता में है। ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। इस कंपनी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को पहले मार्टिन लॉटरी एजेंसीज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। इस जानकारी के मुताबिक ये कंपनी दो अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के कारोबार के साथ भारत के लॉटरी उद्योग में अग्रणी खिलाड़ी है। कंपनी की वेबसाइट पर लिखा है, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (फ्यूचर गेमिंग) ने भारत के विभिन्न लॉटरी खेलने वाले राज्यों में, जहां भी लॉटरी बिक्री की अनुमति है, डीलरों और एजेंटों का एक विशाल नेटवर्क विकसित किया है। इसने लॉटरी के क्षेत्र में निरंतर बाजार अनुसंधान के माध्यम से व्यवसाय में अव्वल है। कंपनी

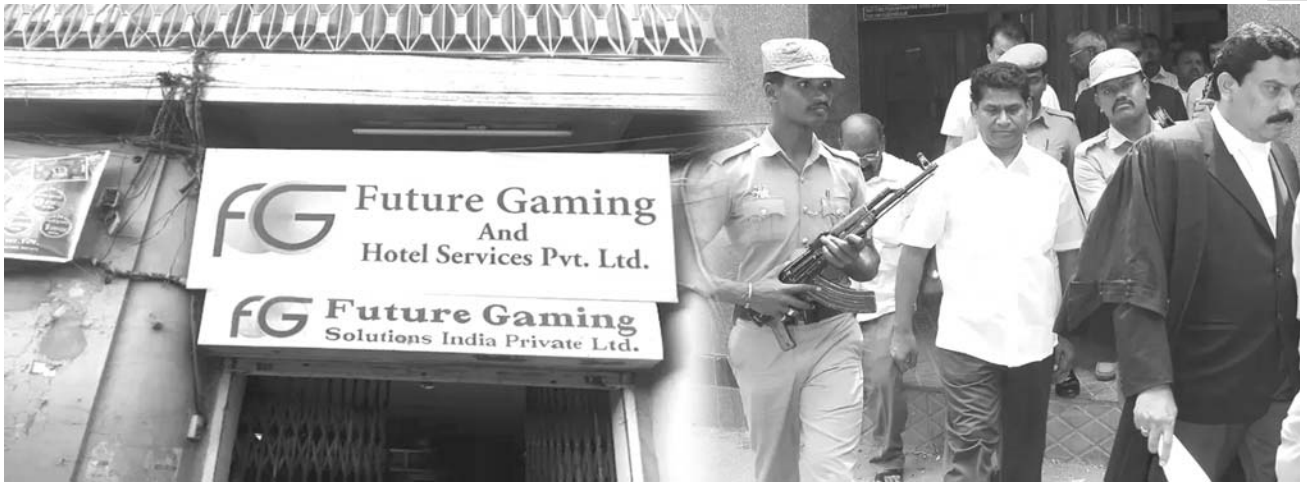

वेबसाइट के मुताबिक 1991 में अपनी स्थापना के बाद से फ्यूचर गेमिंग विभिन्न राज्य सरकारों की पारंपरिक पेपर लॉटरी के वितरण में तेज गति से बढ़ रहा है। यह प्रतिस्पर्धी बोली, आक्रामक मार्केटिंग और भारत के कई राज्यों में कुशल लॉटरी संचालन के साथ-साथ विकास के प्रति ऊर्जावान रवैये के कारण संभव हुआ है। कंपनी वेबसाइट पर ये भी लिखा गया है कि फ्यूचर गेमिंग एशिया पैसिफिक लॉटरी एसोसिएशन (एपीएलए) का सदस्य है और 2001 से फ्यूचर गेमिंग वर्ल्ड लॉटरी एसोसिएशन (डब्लूएलए) का सदस्य है।

☞ **कौन हैं सैंटियागो मार्टिन?** :- उपलब्ध जानकारी के मुताबिक सैंटियागो मार्टिन इस कंपनी के चेयरमैन हैं। मार्टिन को 'लॉटरी किंग' भी कहा जाता है। कंपनी के मुताबिक मार्टिन ने लॉटरी उद्योग में 13 साल की उम्र में कदम रखा और पूरे भारत में लॉटरी के खरीदारों और विक्रेताओं का एक विशाल नेटवर्क बना लिया। कंपनी वेबसाइट के मुताबिक मार्टिन कई बार देश में सबसे ज्यादा आयकरदाता की पदवी से नवाजे गए। मार्टिन चौरिटेबल ट्रस्ट की वेबसाइट के मुताबिक व्यापारिक दुनिया में शामिल होने से पहले मार्टिन ने सबसे पहले म्यांमार के यांगून शहर में एक मजदूर के रूप में अपना करियर शुरू किया था। अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए मामूली वेतन कमाते थे। बाद में, वह भारत वापस आ गए, जहां उन्होंने 1988 में तमिलनाडु में अपना लॉटरी व्यवसाय शुरू किया। धीरे-धीरे कर्नाटक और केरल की ओर विस्तार किया।

☞ **फ्यूचर गेमिंग पर ईडी की कार्रवाई** :- ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत 11 और 12 मई 2023 को फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सैंटियागो मार्टिन और अन्य लोगों के चेन्नई में आवासीय परिसरों और कोयंबटूर में व्यावसायिक परिसरों में तलाशी अभियान चलाया था। तलाशी के दौरान करीब 457 करोड़ रुपये की चल/अचल संपत्ति बरामद की गई। ईडी ने 21 सितंबर 2023 को फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और 15 अन्य कंपनियों के खिलाफ कोलकाता की विशेष पीएमएलए अदालत में अभियोजन शिकायत दायर की जिसका अदालत ने संज्ञान लिया। ईडी ने फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज और अन्य कंपनियों के खिलाफ कोलकाता पुलिस द्वारा दर्ज की गई उन एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिनमें आईपीसी और लॉटरी विनियमन अधिनियम, 1998 की धाराएं लगाई गई थी। ईडी का कहना था कि उसकी जांच में पता चला कि मेसर्स फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने कई राज्य सरकारों से समझौता किया था कि वो उनकी लॉटरियां पूरे देश में बेचेगी। ईडी के मुताबिक इस कंपनी ने कथित तौर पर लॉटरी की बिक्री से मिली संपूर्ण बिक्री आय को जमा न करके लॉटरी जारी करने वाले राज्य को धोखा दिया है। ईडी के मुताबिक इस कंपनी की कार्यप्रणाली में अवैध रूप से बिना बिकी लॉटरी को अपने पास रखना, बिना बिकी लॉटरी पर पुरस्कार का दावा करना, बिना बिके पुरस्कार विजेता टिकटों को बेचा हुआ दिखाने के लिए डेटा में हेरफेर करना और उस पर पुरस्कार का दावा करना भी शामिल है जो लॉटरी विनियमन अधिनियम, 1998 का उल्लंघन था। नौ मार्च को तमिलनाडु में कथित अवैध रेत खनन में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने सैंटियागो मार्टिन के दामाद आधव अर्जुन और उनकी संपत्तियों की भी तलाशी ली थी।

कानूनी सलाह

शिवानंद गिरि

(अधिवक्ता)

Ph.- 9308454485
7004408851

E-mail :-
shivanandgiri5@gmail.com

☆ कब एक पति द्वारा अपनी ही पत्नी के साथ उसके मर्जी से शारीरिक संबंध बनाने पर बलात्कार की कोटि में आता है ?

यदि पत्नी की आयु 15 वर्ष से कम है तो पति द्वारा किया गया मैथुन बलात्कार की श्रेणी में आता है साथी यदि जो कि अपनी पत्नी के साथ जो पृथक्करण की किसी डिक्री के अधीन या किसी प्रकार या रीति रिवाजों के अधीन उससे अलग रह रही हो तो उसकी सहमति के बिना मैथुन करता है तो वैसे पति को 2 वर्षों से लेकर 7 वर्षों तक का कारावास और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है इस अपराध के लिए दंड की व्यवस्था भारतीय दंड संहिता की अधिनियम की धारा 376 ख में किया गया है यह एक संगीन एवं अजमानती अपराध होता है इसकी ट्रायल सेशन न्यायालय में किया जाता है।

☆ अगर कोई जेल का अधीक्षक महिला कैदी के साथ बलात्कार करता है तो उसे कितने वर्षों की सजा हो सकती है?

यदि कोई जेल प्रति प्रेषण गृह आदि के अधीक्षक किसी महिला कैदी के साथ संभोग करता है या कोई लोक सेवक द्वारा किसी स्त्री के साथ संभोग किया जाता है तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 376(ख) या 376(ग) के अनुसार 5 वर्षों तक की सजा एवं जुर्माना से भी दंडित किया जा सकता है।

☆ यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अपराधी को अपने यहां संरक्षण दिया जाता है तो इसके लिए किस प्रकार की सजा का प्रावधान है?

यदि किसी अपराधी ने कोई अपराध किया है तो कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि वह अपराधी है एवं उसने अपराध किया है और उसे अपने यहां संरक्षण देता है तो संरक्षण देने वाला व्यक्ति भी अपराधी माना जाएगा तथा ऐसे व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 212 एवं 216 के तहत सजा दिया जा सकता है यदि भारतीय दंड संहिता की धारा 212 के अनुसार अपराधी द्वारा किया गया अपराध मृत्युदंड से दंडनीय है तो संरक्षण देने वाले को 5 वर्षों तक की सजा और जुर्माना इत्यादि दिया जा सकता है और यदि अपराध आजीवन कारावास से लेकर 10 वर्षों तक के लिए कारावास से दंडनीय है तो उस अधिकतम अवधि की एक चौथाई का कारावास एवं जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है भारतीय दंड संहिता की धारा 216 के अनुसार यदि अपराधी जो की पुलिस कस्टडी से निकल भागा है या जिसे पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है और यदि अपराध मृत्यु दंड से दंडनीय है तो संरक्षण देने वाले को 7 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों प्रकार के दंडो से दंडित किया जा सकता है और यदि अपराध आजीवन कारावास या 10 वर्ष के कारावास से दंडनीय है तो संरक्षण देने वाले व्यक्ति को जुर्माना सहित या जुर्माना रहित 3 वर्ष और यदि 1 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के कारावास से दंडनीय अपराध का अभियुक्त है तो उस अपराध के सजा के दीर्घ अवधि की एक चौथाई का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित संरक्षण देने वाले व्यक्ति को किया जा सकता है।

☆ क्या न्यायालय के खिलाफ पत्रिका या किसी भी मीडिया में समाचार छापना या दिखाना न्यायिक अवमानना का अपराध होता है?

न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 (कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट 1971) की धारा 5 के अनुसार न्यायिक कार्य की उचित आलोचना अवमानना नहीं कहलाती है। इस धारा के अनुसार कोई व्यक्ति किसी ऐसे मामले की जिसकी सुनवाई हो चुकी हो और उसमें न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से फैसला दिया जा चुका हो उसके गुण अवगुण पर किसी उचित आलोचना का प्रकाशन करने या प्रसारण करने पर न्यायालय अवमानना का अपराध नहीं होता है कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट के अपराध मे धारा 12 के अनुसार जो कोई व्यक्ति न्यायालय अवमानना का दोषी पाया जाएगा उसे सादे कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकती है दंडित किया जा सकता है।

☆ किसी आपराधिक मामले की सुनवायी के लिए कोई मजिस्ट्रेट के यहां से अगर किसी दूसरे मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या प्रावधान है?

किसी आपराधिक मामलों की सुनवाई अगर किसी न्यायिक दंडाधिकारी के यहां चल रहा हो और किसी पक्ष कार को यदि है लगता है कि वह कोर्ट दूसरे पक्ष कार के तरफ से काम कर रहे हैं और प्रथम पक्ष कार की बात को नहीं सुना जा रहा है जिसके वजह से उसे न्याय नहीं मिल पाएगा तो इस संबंध में आप मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहां केस्को किसी अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहां ट्रांसफर करवाने के लिए आवेदन दे सकते हैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 410 में यह प्रावधान है कि कोई मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अपने अधीनस्थ किसी न्यायिक दंडाधिकारी से किसी मामले को वापस ले सकता है या किसी मामले को जिसे उसने ऐसे मजिस्ट्रेट के हवाले किया है वापस मंगा सकता है और मामले की जांच या विचारण स्वयं कर सकता है या उसे जांच या विचारण के लिए किसी अन्य ऐसे न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देशित कर सकता है जो उसकी जांच या विचारण करने के लिए सक्षम हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 410(2) मैं यह प्रावधान किया गया है कि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी मामले को जो उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 192 की उप धारा 2 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले किया है वापस मंगा सकता है और ऐसे मामले को जांच या विचारण स्वयं कर सकता है।

GSTIN : 10KEPD0123PIZP

उत्तर भारत का COOKIE MAKER, सीवान में पहली बार
आपके लिए लेकर आया है

Cookie का बेहतर श्रृंखला

PRATIK ENTERPRISES

राजपुर (रघुनाथपुर) में अत्याधुनिक मशीनों द्वारा रस्क, बिस्कुट, बर्गर, मीठा ब्रेड, वंद, क्रीम रोल, पेटीज और बर्ड डे केक, पार्टी केक ग्राहकों के मनपसंद तैयार किया जाता है।

शुद्धता एवं स्वाद की 100% गारंटी

किसी भी अवसर पर
एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।

प्रतीक फुड कंपनी

प्रतीक इंटरप्राइजेज, प्रतीक पतंजलि
राजपुर, रघुनाथपुर, सीवान (बिहार)

-: सौजन्य से :-

ब्रजेश कुमार दुबे

Mob.-9065583882, 9801380138

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.
(Serving nation since 1990)

WESTOCITRON
WESTOCLAV
WESTOFERON
WESTOPLEX
QNEMIC

AOJ
AZIWEST
DAULER
MUCULENT
AOJ-D
BESTARYL-M
GAS-40
MUCULENT-D

SEVIPROT
WESTOMOL
WESTO ENZYME
ZEBRIL

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.
WD
Dispersing Happiness

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.
Industrial area, Fatuha-803201
E-mail- westerlindrugsprivatelimited@gmail.com
Phone No.:0162-3500233/2950008